



श्रमसाधना



हम बनेंगे आपकी आवाज
रकने करें और चैनल से जुड़े

shramsadhnagwl@gmail.com

श्रम की शक्ति, राष्ट्र की प्रगति

www.shramsadhnagnews.com

दैनिक सांध्यकालीन

RNI रजि. क्र. 50069/89

वर्ष: 38, अंक: 89 ग्वालियर, शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत् 2083 पृष्ठ 12, मूल्य 1 रुपया

डाक पंजीयन

L-2-13/समा.पत्र/पं. 40020181/22-23

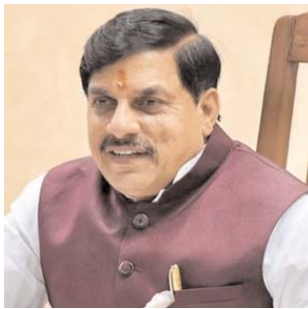
स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री करेंगे भोपाल के विद्यार्थियों को सम्मानित, जिलों में भी एक नवंबर को होगा पुरस्कार वितरण

श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति के 102 विजेता घोषित, मिलेंगे एक-एक लाख रुपए

भोपाल जीएनएस

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर एक नवंबर को प्रदेश के 45 जिलों के 102 मेधावी विद्यार्थियों को भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति के तहत एक-एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भोपाल के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। अन्य जिलों में जिला स्तरीय स्थापना दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।

श्रीकृष्ण पाथेय न्यास ने



छात्रवृत्ति प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर दी है। प्रतिभागियों में से विजेताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। इसमें विद्यालय स्तर के 51 और महाविद्यालय स्तर के 51 विद्यार्थियों को चुना गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को पुरस्कार वितरण की आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। पुरस्कार राशि के चेक और प्रमाण पत्र श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्वालियर से दो विद्यार्थियों का चयन : ग्वालियर जिले से विद्यालय स्तर पर डॉ. भीमराव आंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिवांश पखारिया और महाविद्यालय स्तर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के शौर्य प्रधान को विजेता घोषित किया गया है। दोनों को एक-एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रमाण

पत्र मिलेंगे।

प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को एक नवंबर को संबंधित जिला मुख्यालयों पर आयोजित स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

विद्यालय स्तर के विजेताओं में विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र भी शामिल हैं। वहीं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक और तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों का चयन हुआ है। योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देना है।

मक्का-सोया किसानों के लिए अवकाश में भी खुलेंगी मंडियां

भोपाल जीएनएस

सोयाबीन और मक्का उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब मंडियों के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए अवकाश के दिनों में भी मंडियां खुली रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मंडी बोर्ड ने इस संबंध में सभी संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में इन दिनों अधिसूचित कृषि उपज

की आवक अधिक मात्रा में हो रही है। ऐसे में अवकाश के कारण मंडियां बंद रहने पर किसानों को उपज बेचने के लिए अगले कार्यदिवस तक इंतजार करना पड़ता है। इससे उपज के विक्रय में देरी के साथ किसानों को आर्थिक और व्यावहारिक परेशानी भी होती है। मंडी बोर्ड ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अवकाश के दिनों में भी मंडियों और उपमंडी प्रांगणों में कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था सुचारू रखें।

नगर निगम ने हटाए अस्थाई अतिक्रमण, मुख्य मार्गों पर यातायात कराया सुगम

ग्वालियर जीएनएस

शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने और मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर निगम के मदाखलत अमले ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान यातायात में बाधक हाथ ठेले, फुटपाथ पर लगाए गए फड़ और सड़क पर रखा सामान हटाया गया। अतिक्रमण करने वालों को दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी गई।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देश पर नोडल अधिकारी मदाखलत केशव सिंह चौहान के निर्देशन में मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने

कार्रवाई की। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में झलकारी बाई पार्क के पास बैठे भिक्षुकों को हटाया गया। वहीं, बहोड़ापुर क्षेत्र में सड़क पर खड़े हाथ ठेले और अन्य अस्थाई अतिक्रमण हटाकर आवागमन सुचारू कराया गया।

दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में माधवगंज चौराहे से रॉक्सी पुल तक सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए हाथ ठेलों को हटाया गया। नगर निगम कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों के आधार पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लंपी रोग से ग्रस्त गोवंश को उपचार के लिए रतवाई गौशाला स्थित आइसोलेशन सेंटर पहुंचाया गया।

ग्राम जैत पहुंचकर शोकाकुल परिवार से की मुलाकात, व्यक्ति की संवेदनाएं

शिवराज सिंह चौहान की माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर

ग्वालियर जीएनएस

केंद्रीय मंत्री एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी स्वर्गीय काशीबाई चौहान का भोपाल एम्स में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सीहोर जिले के ग्राम जैत में किया गया। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अंतिम संस्कार में शामिल हुए और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान तोमर ने शिवराज सिंह चौहान और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने परिवार को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।



ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवराज सिंह चौहान की माताजी के निधन पर जताया शोक

ग्वालियर जीएनएस। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी श्रीमती काशीबाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मां परिवार की शक्ति और संस्कारों की आधारशिला होती है। जीवन के हर संघर्ष में मां का स्नेह और आशीर्वाद सबसे बड़ा संबल होता है तथा वही जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। मंत्री तोमर ने कहा कि मां का इस संसार से विदा होना ऐसी पीड़ा है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। उन्होंने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

झांसी रोड पुलिस ने पीड़ित की पूरी रकम वापस कराई, आरोपी के बैंक खाते में अन्य शिकायतों के लाखों रुपए भी मिले

शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 2 लाख टगे, हरियाणा से आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर जीएनएस

ऑनलाइन शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर बिजली विभाग के कर्मचारी से 2 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को झांसी रोड पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरियादी की ठगी गई पूरी रकम भी वापस करा दी है। जांच में आरोपी के बैंक खाते में अन्य लोगों की शिकायतों से संबंधित लाखों रुपए का लेनदेन और होल्ड राशि भी सामने

आई है।

पुलिस के अनुसार, श्रीराम कॉलोनी निवासी विजय कुमार सिंधी बिजली विभाग में कार्यरत हैं। आरोपियों ने उनसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर शेयर बाजार में निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच दिया। इसके बाद उन्हें ए1154 मैगनम ट्रेडर्स हब नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर मैगनम स्मार्ट एप डाउनलोड कराया। निवेश के लिए बताए गए बैंक खाते में फरियादी ने 3 और 4 जून

2026 को दो बार में कुल 2 लाख रुपए जमा किए। एप पर मुनाफा दिखने के बाद जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने 10 लाख रुपए और जमा करने की शर्त रख दी। इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया। ठगी का संदेह होने पर फरियादी ने 5 जून को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर ई-जीरो एफआईआर क्रमांक 854/26 के जरिए झांसी

रोड थाने में अपराध क्रमांक 163/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पलवल का रहने वाला है आरोपी : साइबर तकनीक से जांच के दौरान ठगी की रकम प्राप्त करने वाले बैंक खाते के खाताधारक की पहचान प्रवीण खटीक (32), निवासी सोहना (हरियाणा) के रूप में हुई। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी के संबंध

में अन्य संलिप्त व्यक्तियों और तथ्यों की जांच जारी है।

प्रभारी पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर के निर्देश तथा एसपी डॉ. शिवेश सिंह बघेल और सीएसपी विश्वविद्यालय शैलेन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। इसमें थाना प्रभारी निरीक्षक सुरभि शर्मा, उपनिरीक्षक आशीष शर्मा, प्रधान आरक्षक रामप्रीत तथा आरक्षक इरशाद, पवन, राजकुमार और हरिओम जाट की भूमिका रही।

पुलिस की अपील : पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अधिक मुनाफे के लालच में बिना सत्यापन किसी कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश न करें। अपनी निजी बैंकिंग जानकारी, पिन और पासवर्ड किसी से साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं और नजदीकी थाने में सूचना दें।

सात जिलों में नये वरिष्ठजन आश्रम और तीन जिलों में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित होंगे

जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों को मजबूत बनाएं, निर्बाध संचालन सुनिश्चित करें

भोपाल, जीएनएस। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्री श्री कुशवाह ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) को मजबूत बनाने और उनका निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने

कहा कि केन्द्रों के संचालन में आ रही कठिनाइयों का समाधान कर उनकी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। मंत्री श्री कुशवाह ने डीडीआरसी में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा जिलों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 51 जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 और वर्ष 2025-26 में 37 केन्द्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। केन्द्रों के मानव संसाधन, कार्यों और गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित



की जा रही है। उन्होंने सभी संस्थानों में सतत निगरानी के लिए छठ्ठड़ू कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिये। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्री के.जी. तिवारी ने बताया कि प्रदेश में

संचालित 89 वृद्धाश्रमों में 2,423 वरिष्ठजन निवासरत हैं। केन्द्रीय अनुदान से 22 जिलों में 31 नशामुक्ति केन्द्र संचालित हैं। देवास, शिवपुरी और श्योपुर में नए केन्द्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए

हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह वित्तीय वर्ष 2026-27 में कन्या विवाह योजना से अब तक 12,523 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं और 68.87 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। निकाह योजना में 315 हितग्राहियों पर 1.73 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में 413 तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में 700 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप एवं मोटराइज्ड

ट्राइसिकल वितरण राशि 35 हजार प्रति हितग्राही से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है। योजना के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि पेंशन योजनाओं में 56 लाख 54 हजार 579 हितग्राहियों को प्रतिमाह लगभग 339.23 करोड़ रुपये की राशि प्रतिमाह सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राही को स्थान्तरित की जा रही है। प्रदेश के सात जिलों उमरिया पांडुरा बुरहानपुर मऊगंज अलीराजपुर बड़वानी में वरिष्ठ जन आश्रम प्रारंभ करने किए जाएंगे इसके प्रस्ताव तैयार किए गये हैं।



ऑटो रिक्शाओं एवं माल वाहक वाहनों से वसूला 1.36 लाख का जुर्माना

विशेष अभियान चलाकर की गई ऑटो रिक्शा व माल वाहनों की जाँच

ग्वालियर, जीएनएस। जिले में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सवारी वाहनों की लगातार जाँच की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अभियान बतौर वाहनों की जाँच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराने के निर्देश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को दिए हैं। इस क्रम में बुधवार को ग्वालियर शहर में हजीरा क्षेत्र सहित शहर के अन्य बाजारों में ऑटो रिक्शा वाहनों की फिटनेस, परमिट व पीयूसी इश्योरेस इत्यादि की जाँच

की गई। साथ ही अटल गेट पुरानी छवनी पर माल वाहक वाहनों की जाँच की गई। इस दौरान वाहनों में मियां पाई जाने पर कुल 01 लाख 36 हजार रुपए का जुर्माना (शमन शुल्क) वसूला गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विक्रमजीत सिंह कांग ने बताया कि शहर में ऑटो रिक्शा की चैकिंग के दौरान सुरक्षा मानकों व परमिट इत्यादि में कमी पाई जाने पर 57 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। इसी तरह सभागीय उड़नदस्ते द्वारा अटल गेट पुरानी छवनी पर चार लोडिंग वाहनों में क्षमता से अधिक भार परिवहन करते हुए मिलने पर 79 हजार रुपए के शमन शुल्क की वसूली की गई।

ग्वालियर में भी उत्साह, उमंग व हर्षोल्लास के साथ मनेगा मध्यप्रदेश का 71वाँ स्थापना दिवस

ग्वालियर, जीएनएस। सम्पूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी मध्यप्रदेश का 71वाँ स्थापना दिवस उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया जायेगा। जिले का मुख्य समारोह 01 नवंबर को सांध्यबेला में मेला परिसर में आयोजित होगा। स्थापना दिवस पर

आयोजित होने जा रहे इस समारोह में भारतीय परंपरा, जीवन मूल्यों और संस्कारों पर केन्द्रित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि समारोह स्थल पर सरकार की विभिन्न योजनाओं पर केन्द्रित प्रदर्शनियां लगेगीं। साथ ही विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य कर रहे

कलाकारों, नागरिकों व शासकीय सेवकों को सम्मानित किया जायेगा। स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रहे मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम व लोकतंत्र सेनानियों, जनप्रतिनिधिगणों, शहीदों के परिजनों, उद्यमियों, व्यवसायियों, समाजसेवियों, धर्मगुरु, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्कूली एवं

महाविद्यालयीन विद्यार्थियों, स्व-सहायता समूहों व स्टार्टअप के पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिक इत्यादि को आमंत्रित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने चौहान ने जिलेवासियों से उत्साह व उमंग के साथ प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने की अपील की है।

लेखा प्रशिक्षण के लिए शासकीय कर्मचारी 15 नवम्बर तक कर सकते हैं आवेदन

ग्वालियर, जीएनएस। शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर में विभिन्न शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये लेखा प्रशिक्षण सत्र 01 दिसम्बर से प्रारंभ होगा। लेखा प्रशिक्षण के इच्छुक कर्मचारी 01 से 15 नवम्बर तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन लेखा प्रशिक्षण शाला

में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रवेश पत्र का प्रारूप चंद्रबदनी नाका के समीप न्यू राजस्व भवन के द्वितीय तल पर स्थित लेखा प्रशिक्षण शाला कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण में कर्मचारियों को

हायर सेकेण्ड्री परीक्षा के साथ टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण एवं एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। प्रवेश दिनांक को कर्मचारी की एक वर्ष की नियमित शासकीय सेवा जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क 5000 रुपए का चालान जमा करना होगा। प्रशिक्षण के लिये 40 से 45

वर्ष से अधिक आयु वर्ग पर टाइपिंग परीक्षा से छूट का आदेश / प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो तो आवेदन के साथ और आधारकार्ड की प्रतिलिपि स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के संबंध में अधिक जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जानकारी देने कलेक्ट्रेट में हैल्पडेस्क स्थापित

ग्वालियर, जीएनएस। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित सेवाओं की जानकारी देने के लिये ग्वालियर कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में हैल्प डेस्क स्थापित की गई है। जिसका टेलीफोन नंबर 0751-2446230 व 2426310 है। जिले के नागरिक कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10 बजे से

सायंकाल 6 बजे तक इन टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस हैल्पडेस्क के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम में संशोधन व नाम हटाने सहित मतदाता सूची से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन

व जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण डू 2027 के दौरान मतदाता सूची में अपने नाम की जाँच अवश्य कर लें। साथ ही पात्र होने पर नाम जुड़वाने या फिर आवश्यक संशोधन के लिये निर्धारित प्रक्रिया के तहत

आवेदन अवश्य करें। ज्ञात हो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) के संक्षिप्त पुनरीक्षण डू 2027 घोषित किया गया है। जिसके तहत ग्वालियर जिले में भी 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जायेगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 2 नवंबर

2026 तक मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा। कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर 2026 प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 दावे एवं आपत्तियाँ, 28 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियों का निराकरण एवं 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

भिण्ड-गोरमी
के
समाचार
विज्ञापन
के लिए सम्पर्क करें
महेश चौधरी
98267-36233

श्रीजी
SCAN TO SHOP
Har Khushi Ki Pahali Pasand
Soya Chunks, PASTA, POHA, MAACHA, ATTA
OUR NEW PRODUCT

श्रमसाधना

संपादकीय

मतदाता सूची से नाम हटने की पीड़ा और हाशिए पर खड़ा आम आदमी

लोकतंत्र में मतदान केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिक की पहचान, सम्मान और भागीदारी का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि मतदाता सूची से उसका नाम हटा दिया गया है, तो यह उसके लिए केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं होती, बल्कि अपने ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपेक्षित हो जाने की पीड़ा भी होती है। जिस नागरिक ने वर्षों तक मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत किया, अचानक उसी को अपनी नागरिक भागीदारी साबित करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, तो उसकी बेबसी समझी जा सकती है।

हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की खबरों ने इस प्रश्न को गंभीर बना दिया है। समाचारों के अनुसार, अनेक लोगों को सूची से नाम हटने के बाद दोबारा पंजीकरण कराने और अपनी पात्रता साबित करने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भी लाखों मतदाताओं के नामों के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने की खबर सामने आई है। निर्वाचन संबंधी अभिलेखों को शुद्ध रखना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी योग्य नागरिक का नाम गलती से हट जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

इस समस्या का सबसे अधिक प्रभाव समाज के कमजोर और वंचित वर्गों पर पड़ता है। दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति एक दिन काम छोड़कर सरकारी कार्यालय जाता है, तो उसके परिवार की आमदनी प्रभावित होती है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और अशिक्षित नागरिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाना तथा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना आसान नहीं होता। जिनके पास पर्याप्त समय, संसाधन और प्रशासनिक जानकारी है, वे अपनी समस्या के समाधान का रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन हाशिए पर खड़ा व्यक्ति अक्सर व्यवस्था की जटिलताओं के सामने असहाय हो जाता है।

सबसे अधिक पीड़ा तब होती है, जब वर्षों से मतदान करते आ रहे किसी व्यक्ति को अचानक अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। कहीं किसी जीवित व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, तो कहीं स्थान परिवर्तन या अभिलेखों की त्रुटि के कारण नाम सूची से गायब हो जाता है। निर्वाचन आयोग के अपने दिशा-निर्देश भी नाम हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया, आवश्यक सत्यापन और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने पर बल देते हैं। इसलिए प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जाँच और समयबद्ध समाधान आवश्यक है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट सूचना, सरल आवेदन व्यवस्था और प्रभावी शिकायत निवारण से दोनों उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। नागरिक को यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि उसका नाम किस कारण हटाया गया और उसे पुनः शामिल कराने के लिए क्या करना होगा। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल मतदान के आँकड़ों में नहीं, बल्कि इस विश्वास में निहित है कि प्रत्येक पात्र नागरिक की आवाज का समान महत्व है।

प्रान्तीय कार्यालय : 76 शबरी कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर जोन-2 भोपाल, फोन : 0755-2579530

प्रान्तीय ब्यूरो प्रमुख : एल.एन. तवर, 9827781209

प्रान्तीय ब्यूरो : डॉ. जानकी अहिरवार 9406580345

Email:shramsadhnagwl@gmail.com

दवा कीमतों पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता जायज

सौरभ वाष्णीय

स्वास्थ्य किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी आवश्यकता है और जीवन बचाने वाली दवाओं तक सुलभ पहुंच प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति इलाज के खर्च के सामने बेबस हो जाए, तब स्वास्थ्य व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की कीमतों में कथित भारी अंतर पर जो गंभीर चिंता जताई है, वह केवल दवा बाजार की अनियमितताओं का मामला नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य, सरकारी जवाबदेही और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा एक व्यापक प्रश्न है। अदालत के समक्ष कैंसर के एक इंजेक्शन का उदाहरण आया, जिसकी कीमत लगभग ग्यारह हजार रुपये बताई गई, जबकि निजी अस्पताल में उसी इंजेक्शन के लिए डेढ़ लाख रुपये वसूले जाने की बात सामने आई। यदि इन आंकड़ों की पुष्टि होती है, तो यह अंतर निश्चित रूप से जांच और जवाबदेही की मांग करता है।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज और उसके परिजन पहले ही मानसिक, शारीरिक बेदना सहित आर्थिक संकट से गुजरते हैं। ऐसे समय में इलाज का खर्च उनकी परेशानी को कई गुना बढ़ा देता है। परिवार अपनी बचत खर्च करता है, संपत्ति बेचने को मजबूर होता है और कई बार उधार लेकर उपचार कराता है। यदि किसी दवा की खरीद कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली राशि के बीच असाधारण अंतर है, तो यह जानना आवश्यक है कि उस अंतर में दवा की वास्तविक लागत, अस्पताल का खर्च, भंडारण, आपूर्ति, कर, सेवा शुल्क और अन्य मदों का कितना योगदान है।

यह समझना भी जरूरी है कि दवा की निर्माता कीमत, वितरक की कीमत,

अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी और अस्पताल द्वारा मरीज से वसूली जाने वाली राशि हमेशा एक समान नहीं होती। अस्पताल में दवा देने, उसे सुरक्षित रखने, निगरानी करने और उपचार संबंधी सेवाओं का खर्च भी हो सकता है। लेकिन इन खर्चों के नाम पर यदि बिना उचित आधार के कई गुना रकम वसूली जाती है, तो उसे सामान्य व्यावसायिक गतिविधि मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मरीज को स्पष्ट बिल, मूल्य का उचित विवरण और इलाज से संबंधित खर्चों की पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की भूमिका और दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। यह चिंता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दवाओं के मूल्य निर्धारण और आवश्यक औषधियों की उपलब्धता में सरकार की भूमिका निर्णायक होती है। जब बाजार में जीवनरक्षक दवाओं के दाम आम नागरिक की पहुंच से बाहर होने लगे, तब केवल नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा होनी चाहिए।

भारत में आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश और राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इनके माध्यम से निर्धारित दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निगरानी व्यवस्था मरीजों तक पर्याप्त राहत पहुंचा पा रही है? क्या मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर रहने वाली दवाओं और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उत्पादों की कीमतों पर पर्याप्त पारदर्शिता है? क्या नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध समय पर

कार्रवाई होती है? इन सवालों के जवाब केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि मरीजों के वास्तविक अनुभवों और स्वतंत्र जांच से भी मिलने चाहिए।

अदालत में सलाइन ड्रिप, हार्ट स्टेंट और एंटीबायोटिक जैसी वस्तुओं की कीमतों के उदाहरण भी सामने आए। बताया गया कि लगभग 11 रुपये की सलाइन ड्रिप 270 रुपये में, पांच हजार रुपये का हार्ट स्टेंट 25 हजार रुपये से अधिक में और 28 रुपये की एंटीबायोटिक एंजिथ्रोमाइसिन 70 रुपये से अधिक में बेची जा रही है। इन आंकड़ों को संबंधित उत्पादों, उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, कर, आपूर्ति और बिक्री के स्तर के संदर्भ में सत्यापित करना जरूरी है। फिर भी यदि समान उत्पादों की खरीद और बिक्री कीमतों में इतना बड़ा अंतर पाया जाता है, तो नियामक संस्थाओं को उसका स्पष्ट कारण सामने रखना चाहिए।

विशेष रूप से हार्ट स्टेंट और कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं के मामले में मूल्य पारदर्शिता का महत्व और बढ़ जाता है। मरीज अक्सर चिकित्सक की सलाह पर निर्भर होता है और उसे बाजार में विकल्पों की तुलना करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। ऐसे में उसकी मजबूरी का लाभ उठाने की किसी भी संभावना को रोकना सरकार, अस्पताल प्रशासन और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। दवा उद्योग अनुसंधान, नई दवाओं के विकास, उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनियों को उचित लाभ कमाने का अधिकार है, लेकिन जीवनरक्षक दवाओं का बाजार सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार से अलग है। यहां ग्राहक के पास कई बार खरीद टालने या सस्ता विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। गंभीर बीमारी में दवा का विकल्प सीमित हो सकता है और उपचार में देरी जानलेवा साबित हो

सकती है। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बाजार की शक्तियों के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रभावी सरकारी नियमन का संतुलन आवश्यक है।

केंद्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया के कई देशों की तुलना में कम हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलना अपने स्थान पर उपयोगी हो सकती है, लेकिन भारतीय मरीज की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी दवा का दूसरे देश की तुलना में सस्ता होना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसकी कीमत हर भारतीय परिवार की पहुंच में है। असली कसौटी यह होनी चाहिए कि मरीज को आवश्यक उपचार कितने खर्च में, कितनी आसानी से और कितनी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो रहा है। सरकार को दवाओं की कीमतों और अस्पतालों में होने वाली वसूली की नियमित जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कीमत, मरीज से वसूली गई कीमत तथा सेवा शुल्क का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आवश्यक दवाओं की सूची और मूल्य नियंत्रण की समीक्षा समय-समय पर होनी चाहिए। जहां असामान्य मूल्य अंतर सामने आए, वहां निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही, मरीजों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और अनुचित वसूली पाए जाने पर उचित कार्रवाई की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का वास्तविक महत्व तभी सिद्ध होगा, जब उससे व्यवस्था में ठोस सुधार का रास्ता खुले। केवल टिप्पणियों से मरीजों का आर्थिक बोझ कम नहीं होगा। इसके लिए सरकार, दवा कंपनियों, अस्पतालों और नियामक संस्थाओं को जवाबदेह बनाना होगा।

बसों में शहर-गांव का सफर सुविधाजनक बना रही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

मध्यप्रदेश सरकार आम लोगों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती बस परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश परिवहन विज्ञान 2030-31 के तहत शहरों से लेकर गांवों तक बस सेवाओं का विस्तार करने, यात्रियों को निर्धारित समय पर बस उपलब्ध कराने, डिजिटल और मोबाइल ऐप आधारित टिकिट व्यवस्था लागू करने और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों की यात्रा को आसान बनाना और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। यात्री परिवहन विज्ञान समिट-2026 की अनुशंसाओं के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में 351 बसें मध्यप्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में दौड़ रही हैं। योजना

अंतर्गत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में डिजिटल तकनीक से बस यात्रियों का टिकिट लेने का अनुभव आसान हो रहा है। साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर की सिटी बसों में 'चलो' मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टिकिट बुकिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

5,000 से अधिक बस मार्ग होंगे विकसित, 30 लाख से ज्यादा यात्रियों को मिलेगी सुविधा

मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड के विज्ञान 2030-31 के तहत प्रदेश में सार्वजनिक बस परिवहन का व्यापक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 15,000 से अधिक सार्वजनिक बसों का संचालन होगा और 5,000 से अधिक बस मार्ग विकसित किए जाएंगे। विज्ञान के अनुसार, प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को बस सेवा से जोड़ने का

लक्ष्य है। प्रदेश में 180 से अधिक बस डिपो एवं टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस नेटवर्क से सीधा जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, रोजगार, इलाज, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

मोबाइल पर मिलेगी बसों की लोकेशन, डिजिटल टिकिटिंग की सुविधा

प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत यात्रियों को मोबाइल पर बसों की लोकेशन, उनके आने-जाने का समय और निर्धारित मार्ग की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इंदौर में सिटी बस यात्रियों के लिए बस पास की व्यवस्था भी की गई है। डिजिटल

टिकट और ऑनलाइन भुगतान से यात्रियों के लिए टिकट लेना आसान हुआ है। टिकटों की डिजिटल निगरानी से किराये से होने वाली आय में पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बसों में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा प्रणालियां लगाने से यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है।

पीपीपी मॉडल से बसों का संचालन -प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत निजी बस संचालकों का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। बसों के संचालन, समय-सारणी, यात्री सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। बस संचालकों को बसों के रखरखाव, चार्जिंग और संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

भेदभाव मिटाकर समरस समाज की रचना करना संत रविदास जी का संदेश: सुधीर कुमार आर्य

सरस्वती विद्यापीठ में संत रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर व्याख्यानमाला आयोजित, विद्यार्थियों को दिया समरस समाज निर्माण का संदेश

शिवपुरी, जीएनएस।

संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने अपने विचारों, वाणी और आचरण के माध्यम से समाज को समानता, बंधुत्व और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव एवं ऊँच-नीच की भावना से मुक्त समाज की कल्पना प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर प्राप्त हों। वर्तमान समय में भी उनके विचार सामाजिक समरसता स्थापित करने तथा मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में प्रासंगिक हैं।

विद्यार्थियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने व्यवहार में समता, सेवा और सद्भाव के भाव विकसित करने चाहिए। यह विचार मंडल महामंत्री एवं पार्षद श्री सुधीर कुमार आर्य ने व्यक्त किए।

विद्या भारती मध्यभारत प्रांत की योजनानुसार संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय, शिवपुरी में आयोजित व्याख्यानमाला सप्ताह के तृतीय दिवस पर विशेष व्याख्यान कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सुधीर कुमार



आर्य, विशिष्ट अतिथि सेवा क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्रीय संयोजक श्री पुरुषोत्तम जोशी तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रबंधक श्री पवन शर्मा उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि श्री सुधीर कुमार आर्य ने संत रविदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि अथवा बाहरी पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके गुणों, कर्मों और आचरण के

आधार पर किया जाना चाहिए। संत रविदास जी ने अपने जीवन के माध्यम से यह स्थापित किया कि प्रेम, सदाचार और मानवीय संवेदना ही एक श्रेष्ठ समाज की वास्तविक पहचान हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यालय में प्राप्त शिक्षा तभी सार्थक होती है, जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई दे। हमें अपने सहपाठियों एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और भेदभाव से दूर

रहते हुए सहयोग, सेवा तथा सद्भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यही संत रविदास जी के प्रति सच्चा सम्मान और उनके विचारों का वास्तविक अनुसरण होगा। विशिष्ट अतिथि श्री पुरुषोत्तम जोशी ने कहा कि भारतीय संत परंपरा ने सदैव समाज को एकता, सदाचार और मानवीय मूल्यों का मार्ग दिखाया है। संत रविदास जी का जीवन इस परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनके विचार विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता, नैतिकता और समरसता की भावना विकसित करने में सहायक हैं। उन्होंने ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण एवं सर्वांगीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए विद्यालय के प्राचार्य श्री लोकेन्द्र

सिंह मेवाड़ा ने अतिथियों का परिचय कराया तथा व्याख्यानमाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन प्रसंगों एवं विचारों से परिचित होना विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। इन आदर्शों को व्यवहार में अपनाकर ही संस्कारवान, जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्य, दीदी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। व्याख्यानमाला के माध्यम से विद्यार्थियों को संत रविदास जी के विचारों को समझने तथा समानता, सामाजिक सद्भाव, सेवा एवं मानवता के मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिली। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन विद्यालय के आचार्य श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने किया।

लाल सिंह आर्य ने हॉकी प्रशिक्षक अविनाश भटनागर का किया सम्मान

ग्वालियर, जीएनएस।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य द्वारा हॉकी प्रशिक्षक श्री अविनाश भटनागर का सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री भटनागर के हॉकी खेल के क्षेत्र में योगदान एवं खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की गई।

श्री अविनाश भटनागर खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ग्वालियर में एन.आई.एस. योग्यताप्राप्त हॉकी प्रशिक्षक के रूप में लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। वे दर्पण हॉकी फीडर सेंटर के माध्यम से युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बालिका हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा निखारने तथा उन्हें राज्य, राष्ट्रीय एवं



अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेक खिलाड़ियों ने विभिन्न स्तरों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हॉकी के जमीनी स्तर पर विकास, नई प्रतिभाओं को तलाशने और आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को खेल के

लिए प्रोत्साहित करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री लाल सिंह आर्य द्वारा किया गया यह सम्मान श्री अविनाश भटनागर के लिए गौरव का विषय है। यह सम्मान हॉकी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाला है।

झगड़ा कर रहे पिता पुत्र सहित तीन लोगों को चौकी प्रभारियों ने गिरफ्तार कर शांति भंग में किया चालान

जालौन, जीएनएस।

नगर में एक व्यक्ति को पड़ोसी से झगड़ा करना तथा एक ग्राम में पिता पुत्र आपस में झगड़ा करना समेत तीनों को महंगा पड़ा वही चौकी प्रभारियों ने अलग-अलग जगह से उपरोक्त तीनों को गिरफ्तार कर जुर्मा धारा 170 126 135 के तहत अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में जेल भेजा।

रामगंज चौकी प्रभारी विशाल भड़ाना पुलिस बल के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे वही झगड़े की सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम ने रामगंज निवासी ओम सिंह पुत्र संतोष सिंह गाली गलौज कर झगड़ा कर रहा था तभी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर कोतवाली के

हवालात में बंद किया इसी क्रम में ज्ञान भारती चौकी प्रभारी विपिन यादव पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे वही झगड़े की सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम ने ग्राम जौल्हपुर निवासीगण ठाकुरदास पुत्र विश्वनाथ राजेश पुत्र विश्वनाथ पिता पुत्र गाली गलौज कर आपस में झगड़ा कर रहे थे तभी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर कोतवाली के हवालात में बंद किया उक्त घटना में कालपी पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अलग-अलग चालानी रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में डाकटरी परीक्षण कराकर संबंधित अदालत में प्रस्तुत किया।

सपा प्रत्याशी एमएलसी जीत पर स्थानीय पार्टी जनों ने जमकर जश्न मनाया

जालौन। सपा पार्टी स्नातक प्रत्याशी जीत पर पार्टी के लोगों ने गोले दाग कर एक दूसरे को मुंह मीठा कर जमकर खुशी मनाकर अखिलेश यादव डॉक्टर मानसिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। बुधवार की शाम मोहल्ला टरननगंज स्थित चौराहे में वरिष्ठ सपा नेता हरिमोहन सिंह यादव सपा नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव संयुक्त अगवाई में पार्टी के लोगों के साथ सपा पार्टी के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मानसिंह यादव की जीत पर खुशी मनाकर एक दूसरे को जीत की जमकर बधाइयां दी जश्न मनाने वालों में उमदेश सिंह यादव अनुसूचित मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राजकुमार बाल्मीक अमर सिंह यादव सभासद रज्जू सेठ सभासद इकबाल अहमद अधिवक्ता सभासद प्रतिनिधि शिवकुमार आदि।

कैट के प्रदेश सचिव राजेश अग्रवाल बने गुना शिवपुरी जिले के प्रभारी



गुना, जीएनएस।

देश की अग्रणी व्यापारिक संस्था कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स -कैट- द्वारा राजेश अग्रवाल को उनकी संगठनात्मक सूझबूझ के चलते गुना एवं शिवपुरी जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कैट के प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार गुप्ता प्रिंस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन की सहमति से प्रदेश सचिव राजेश अग्रवाल को गुना एवं शिवपुरी दो जिले का प्रभारी घोषित किया गया है। वर्तमान में कई धार्मिक,

सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों का नेतृत्व कर रहे राजेश अग्रवाल एक लम्बे समय से व्यापारियों एवं आमजन की समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष रखते आ रहे हैं और अपनी साफ सुथरी छवि, कुशल कार्यशैली से समस्याओं का त्वरित निराकरण भी करते हैं।

राजेश अग्रवाल के प्रभारी नियुक्त होने से दोनों जिले के व्यापारियों में हर्ष की लहर व्याप्त है एवं सभी के द्वारा बधाईयां प्रेषित की जा रही हैं।

धनतेरस पर नागाजी मंदिर में भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा

1100 दीपकों से जगमगाएगा केला देवी व श्री नागाजी मंदिर परिसर

पोरसा, जीएनएस।

धनतेरस के पावन पर्व पर दिनांक 6 नवंबर को नागाजी मंदिर परिसर स्थित राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर में भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में भगवान धन्वंतरि के साथ मंदिर परिसर में विराजमान सभी देवी-देवताओं की विधि-विधान से पूजा की जाएगी। श्रद्धालु भगवान से दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और निरोगी जीवन की मंगलकामना करेंगे। आयोजन के दौरान 1100 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में आलोकित होगा।

यह धार्मिक कार्यक्रम *केला देवी भक्त मंडल एवं केला देवी महिला भक्त मंडल* के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर महंत राम लखन दास महाराज बतौर अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं, पुजारी रामदास

श्रोत्रिय महाराज के मार्गदर्शन में पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। आयोजन को लेकर भक्त मंडल के सदस्यों और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहेगा।

भगवान धन्वंतरि की पूजा कर मांगा जाएगा आरोग्य का आशीर्वाद

धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का देवता माना जाता है और श्रद्धालु उनसे स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इसी धार्मिक भावना के साथ नागाजी मंदिर परिसर स्थित राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर में भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।

इस अवसर पर मंदिर परिसर में विराजमान भगवान बांके बिहारी, राम दरबार, भगवान श्री गणेशजी

रिद्धि-सिद्धि महारानी, मां सरस्वती, महादेव बाबा एवं भगवान शंकर तथा बजरंगबली महाराज, एवं श्री नागाजी महाराज सहित सभी देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाएगी। श्रद्धालु परिवार की खुशहाली, समाज की सुख-समृद्धि और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे।

सप्त 1100 दीपक प्रज्वलित कर की जाएगी मंगलकामना

धार्मिक आयोजन का विशेष आकर्षण 1100 दीपकों का प्रज्वलन रहेगा। दीप प्रज्वलन के माध्यम से श्रद्धालु सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना करेंगे। दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण निर्मित होगा और श्रद्धालु श्रद्धा एवं भक्ति के साथ धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। केला देवी भक्त मंडल एवं केला देवी महिला भक्त मंडल के तत्वावधान में आयोजित इस

कार्यक्रम का उद्देश्य धनतेरस के पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरि की आराधना के साथ सभी देवी-देवताओं का पूजन कर जनकल्याण और निरोगी जीवन की मंगलकामना करना है।

कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में अरुण कुमार गुप्ता, महावीर बंसल, अंकुर सिंघल, कन्हैया गुप्ता, रामकुमार गुप्ता, विनोद बंसल, रेखा गुप्ता, सुनीता वर्मा, प्रवेश गुप्ता, आशा गुप्ता एवं पवन गुप्ता सहित अनेक भक्तगण अपनी सहभागिता निभाएंगे। भक्त मंडल के सदस्य आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं को संभालेंगे, ताकि पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम श्रद्धा और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। 6 नवंबर धनतेरस के इस पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरि की आराधना और 1100 दीपकों के प्रज्वलन के साथ श्रद्धालु निरोगी काया, दीर्घायु, सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करेंगे।

इंजीनियरिंग शिक्षा में पृथ्वी विज्ञान, ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच सेतु

डॉ. विजय गर्ग

इंजीनियरिंग केवल गणित, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का नाम नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संसार को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके कार्य करने की कला भी है। प्रत्येक सड़क, पुल, बाँध, सुरंग, भवन और बिजलीघर किसी न किसी रूप में पृथ्वी से जुड़ा होता है। इसलिए सुरक्षित बुनियादी ढाँचे के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए इंजीनियरों को पृथ्वी विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। इंजीनियरिंग शिक्षा में पृथ्वी विज्ञान को शामिल करके सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है।

पृथ्वी विज्ञान में भूविज्ञान, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान और इनसे संबंधित अन्य विषय शामिल हैं। ये विषय पृथ्वी की संरचना, जल की गति, चट्टानों के निर्माण, मिट्टी के गुणों तथा हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जानकारी देते हैं। यह ज्ञान इंजीनियरों को निर्माण कार्य, संसाधन प्रबंधन और सतत विकास से संबंधित उचित निर्णय

लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

पृथ्वी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में होता है। किसी भवन, पुल, राजमार्ग या बाँध का निर्माण करने से पहले इंजीनियरों के लिए उस स्थान की भूवैज्ञानिक विशेषताओं को समझना आवश्यक है। मिट्टी की मजबूती, भूजल का स्तर, चट्टानों की संरचना और भूस्खलन की संभावना किसी भी संरचना की स्थिरता को प्रभावित करती है। भूवैज्ञानिक जाँच के अभाव में नींव कमजोर हो सकती है, संरचनाओं को नुकसान पहुँच सकता है और महँगी मरम्मत की आवश्यकता पड़ सकती है। भूविज्ञान और मिट्टी के व्यवहार का अध्ययन करके इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जोखिमों का आकलन करना तथा अधिक सुरक्षित डिजाइन तैयार करना सीखते हैं।

आपदा प्रबंधन में भी पृथ्वी विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्री तटों का कटाव भारी मानवीय तथा आर्थिक क्षति पहुँचा सकते हैं। भूवैज्ञानिक जोखिमों का ज्ञान रखने वाले इंजीनियर भूकंपरोधी भवनों, बेहतर जल निकासी प्रणालियों, सुरक्षा बाँधों और

मजबूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर सकते हैं। स्थानीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को समझने से योजनाकार जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और वहाँ अनुचित निर्माण से बच सकते हैं। भारत जैसे भौगोलिक विविधता वाले देश में यह अंतर्विषयी ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी है।

जल संसाधनों का प्रबंधन पृथ्वी विज्ञान और इंजीनियरिंग के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण संबंध है। जल विज्ञान और भूजल विज्ञान वर्षा के स्वरूप, नदी प्रणालियों, भूजल की गति और जलभृतों की विशेषताओं को समझने में सहायता करते हैं। यह ज्ञान जलाशयों, सिंचाई प्रणालियों, जल निकासी और टिकाऊ जलापूर्ति परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिर रहा है और वर्षा अनियमित होती जा रही है। ऐसी स्थिति में भावी इंजीनियरों को जल की उपलब्धता, भूवैज्ञानिक संरचनाओं और मानवीय गतिविधियों के बीच संबंध समझना चाहिए।

पर्यावरण इंजीनियरिंग को भी पृथ्वी विज्ञान की शिक्षा से महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। खनन, औद्योगिक विकास, शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के

विस्तार से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं, भूजल दूषित हो सकता है और मिट्टी का कटाव तेज हो सकता है। पर्यावरणीय भूविज्ञान का ज्ञान इंजीनियरों को इन प्रभावों का आकलन करने तथा व्यावहारिक समाधान विकसित करने में सहायता करता है। विद्यार्थी प्रदूषित स्थलों की जाँच, निर्माण अपशिष्ट के प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के तरीके सीख सकते हैं। इससे केवल तकनीकी दक्षता के बजाय जिम्मेदार विकास को बढ़ावा मिलता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी विज्ञान की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। बढ़ता तापमान, वर्षा के बदलते स्वरूप, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि बुनियादी ढाँचे की योजना के सामने नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इंजीनियरों को बाढ़ के बदलते जोखिम, तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता, जल संकट और संरचनाओं की दीर्घकालिक मजबूती को ध्यान में रखना चाहिए। जलवायु वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच सहयोग से जलवायु-अनुकूल शहरों, टिकाऊ परिवहन

नेटवर्क और बेहतर आपदा तैयारी की योजनाएँ विकसित की जा सकती हैं।

इतनी महत्ता के बावजूद कुछ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पृथ्वी विज्ञान को सीमित स्थान मिलता है। विद्यार्थी वैज्ञानिक सिद्धांत तो सीखते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। इस कमी को दूर करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, प्रयोगशाला परीक्षण, पर्यावरणीय सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग विफलताओं के अध्ययन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भौगोलिक सूचना प्रणाली (टिफ़्स), रिमोट सेंसिंग और त्रि-आयामी भूवैज्ञानिक मॉडलिंग जैसे डिजिटल साधन भी व्यावहारिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

विश्वविद्यालयों को सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग, भूविज्ञान और भूभौतिकी विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। उद्योगों के साथ साझेदारी और अंतर्विषयी अनुसंधान परियोजनाएँ विद्यार्थियों को वास्तविक इंजीनियरिंग चुनौतियों से परिचित करा सकती हैं। मूल्यांकन प्रणाली में भी आलोचनात्मक चिंतन, क्षेत्रीय

निरीक्षण और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को महत्व दिया जाना चाहिए।

अंततः, इंजीनियरिंग शिक्षा का उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण करने वाले स्नातक तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे पेशेवर विकसित करना भी है जो उन संरचनाओं के आसपास के भू-दृश्य, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को समझ सकें। पृथ्वी विज्ञान यह आवश्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। भूवैज्ञानिक ज्ञान और इंजीनियरिंग के व्यावहारिक अनुप्रयोग को जोड़कर शिक्षण संस्थान ऐसे इंजीनियर तैयार कर सकते हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों।

पृथ्वी वह आधार है, जिस पर इंजीनियरिंग की पूरी इमारत खड़ी है। इसे समझना इंजीनियरिंग शिक्षा में कोई वैकल्पिक विषय नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, टिकाऊ और आपदाओं का सामना करने में सक्षम विश्व के निर्माण की अनिवार्य शर्त है।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य 7 प्रख्यात वैज्ञानिक स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब डू 152107 मोबाइल-9465682110

बॉलीवुड और क्रिकेट से आगे : क्या वैज्ञानिक बन सकते हैं भारत के नए आदर्श?

डॉ. विजय गर्ग

फिल्मी सितारों, क्रिकेट के नायकों और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हस्तियों के प्रति आकर्षित समाज में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है-क्या वैज्ञानिक भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं? क्या युवा किसी भौतिक विज्ञानी को उतने ही उत्साह से पसंद कर सकते हैं, जितना किसी फिल्म अभिनेता को करते हैं? क्या अंतरिक्ष वैज्ञानिक की उपलब्धियों पर भी क्रिकेट चैंपियन की तरह गर्व किया जा सकता है? क्या युवा केवल प्रसिद्ध होने के बजाय नई खोजें करने के सपने देख सकते हैं? चीन में वैज्ञानिकों को मिल रही बढ़ती सार्वजनिक पहचान ने इन प्रश्नों को चर्चा का विषय बनाया है। यह भारत के लिए भी अपनी प्रसिद्धि की संस्कृति, शैक्षिक प्राथमिकताओं और युवा पीढ़ी के आदर्शों पर पुनर्विचार करने का अवसर है।

सेलिब्रिटी संस्कृति अपने आप में बुरी नहीं है। सिनेमा, खेल और मनोरंजन हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। भारतीय

अभिनेताओं और क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। लेकिन जब मनोरंजन जगत की हस्तियों को अत्यधिक ध्यान मिलता है, जबकि मानव जीवन को बेहतर बनाने वाले वैज्ञानिक गुमनाम रह जाते हैं, तब समाज की प्राथमिकताओं पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। नई दवाएँ विकसित करने वाले, अंतरिक्ष की खोज करने वाले, कृषि में सुधार लाने वाले और भविष्य की तकनीकें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को अक्सर उनके योगदान की तुलना में बहुत कम सार्वजनिक पहचान मिलती है।

चीन में वैज्ञानिक उपलब्धियों पर बढ़ता जोर यह दिखाता है कि लोगों की प्रशंसा को बौद्धिक उपलब्धियों की ओर कैसे मोड़ा जा सकता है। बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं, तकनीकी नवाचारों और अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े वैज्ञानिक तथा इंजीनियर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन रहे हैं। सार्वजनिक अभियान, शैक्षिक पहल और मीडिया कवरेज शोधकर्ताओं को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना सकते हैं।

इससे एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि वैज्ञानिक उपलब्धियाँ केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे किसी देश की पहचान, आत्मविश्वास और प्रगति में भी योगदान देती हैं।

क्या भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ सकता है? निश्चित रूप से। लेकिन इसके लिए कुछ समय के प्रचार अभियान के बजाय निरंतर और सुनियोजित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

भारत की वैज्ञानिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। सी. वी. रमन, होमी जहाँगीर भाभा और डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और कल्पनाशीलता से समाज को बदला जा सकता है। डॉ. कलाम विशेष रूप से लोकप्रिय हुए, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ विद्यार्थियों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को जोड़ा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई वैज्ञानिक पारंपरिक सेलिब्रिटी संस्कृति पर निर्भर हुए बिना भी लोगों का प्रेम और

सम्मान प्राप्त कर सकता है।

अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की उपलब्धियाँ भी इस दिशा में नए अवसर प्रदान करती हैं। चंद्रयान मिशन, सूर्य के अध्ययन के लिए सफल आदित्य-एल1 मिशन तथा देश की बढ़ती वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं ने लोगों में उत्साह पैदा किया है। इसरो के वैज्ञानिक पहले से अधिक पहचाने जाने लगे हैं और उनकी उपलब्धियों ने देशभर के विद्यार्थियों को प्रेरित किया है। फिर भी, लोगों का ध्यान अक्सर किसी मिशन की अंतिम सफलता पर केंद्रित रहता है, जबकि उसके पीछे काम करने वाले वैज्ञानिकों, वर्षों के अनुसंधान, असफल प्रयोगों और कठिन निर्णयों के बारे में कम चर्चा होती है।

भारत को वैज्ञानिक सफलताओं के कभी-कभार होने वाले उत्सवों से आगे बढ़कर विज्ञान के प्रति सम्मान की स्थायी संस्कृति विकसित करनी चाहिए। इसकी शुरुआत विद्यालयों से होनी चाहिए। बच्चों को वैज्ञानिकों के बारे में केवल पाठ्यपुस्तकों में लिखे नामों और तस्वीरों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा, साहस और

रचनात्मक सोच के जीवंत उदाहरणों के रूप में जानने का अवसर मिलना चाहिए। विद्यालयों में विज्ञान मेले, नवाचार प्रदर्शनियाँ, वैज्ञानिक व्याख्यान और शोधकर्ताओं के साथ संवाद आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को समझाया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक खोजें प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, गलतियों से सीखने और निरंतर प्रयास करने से संभव होती हैं।

शिक्षक वैज्ञानिक अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिजली के पाठ के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ विकसित करने वाले इंजीनियरों के बारे में बताया जा सकता है। बीमारियों पर चर्चा करते समय टीकों की खोज की प्रक्रिया समझाई जा सकती है। खगोल विज्ञान की कक्षाओं में भारत के अंतरिक्ष अभियानों के पीछे काम करने वाले वैज्ञानिकों का परिचय दिया जा सकता है। ऐसे अनुभव विज्ञान को रोचक बनाने के साथ विद्यार्थियों को वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

मीडिया की भी इसमें

महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। टेलीविजन चैनलों, समाचार पत्रों, डिजिटल मंचों और सोशल मीडिया को वैज्ञानिकों, उनकी खोजों और जीवन यात्राओं को नियमित रूप से प्रमुखता देनी चाहिए। साक्षात्कारों में केवल उपलब्धियों ही नहीं, बल्कि चुनौतियों, असफलताओं और नैतिक दुविधाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। वृत्तचित्र, पॉडकास्ट, छोटे वीडियो और सरल विज्ञान कार्यक्रमों के माध्यम से जटिल विषयों को आम लोगों के लिए समझने योग्य बनाया जा सकता है। फिल्में और वेब सीरीज भी इस अभियान को मजबूत कर सकती हैं। वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और भारतीय अनुसंधान संस्थानों पर आधारित रचनाएँ मनोरंजन के साथ वैज्ञानिक प्रेरणा भी दे सकती हैं। वैज्ञानिकों को समाज से कटे हुए या नीरस व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें कल्पनाशील, दृढ़ निश्चयी और सामान्य मनुष्यों की तरह भावनाएँ रखने वाले व्यक्तियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए। वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए साहस, त्याग और खोज की रोमांचक कहानियों में बदला जा सकता है।

केआरजी कॉलेज में 'जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद' कार्यशाला, 150 छात्राओं ने लिया भाग; थाना कंपू का भी किया शैक्षणिक भ्रमण

साइबर सुरक्षा से लेकर संविधान तक, छात्राओं को दी कानून की जानकारी

ग्वालियर जीएनएस
मध्यप्रदेश पुलिस और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित 'जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद' अभियान के तहत बुधवार को शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (केआरजी कॉलेज) में विधिक एवं सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें करीब 150 छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस की छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल संरक्षण, संविधान, मानसिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और आपराधिक न्याय व्यवस्था सहित

आठ विषयों पर जानकारी दी गई। अभियान के नोडल अधिकारी एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने छात्राओं को भारतीय संविधान, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों, बाल अधिकारों, किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए छात्राओं से जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनकर सुरक्षित समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का दायित्व अपराध



नियंत्रण के साथ नागरिकों में सुरक्षा की भावना विकसित करना और जरूरत के समय सहायता उपलब्ध कराना भी है। कार्यशाला में एसडीओपी

घाटीगांव शैलेन्द्र शर्मा और निरीक्षक दीपि तोमर ने महिला एवं बाल संरक्षण, उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा ने साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा, यातायात

सूबेदार आयुष मिश्रा ने सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति, निरीक्षक रेडियो भारत सिंह ने आपातकालीन पुलिस सहायता एवं आपदा प्रबंधन तथा एडीपीओ मुरारी लाल गुप्ता ने आपराधिक न्याय व्यवस्था की जानकारी दी। अन्य सत्रों में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और आत्महत्या रोकथाम पर भी चर्चा हुई। प्रश्नोत्तर सत्र में छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

छात्राओं ने थाना कंपू की कार्यप्रणाली समझी : अभियान के तहत केआरजी कॉलेज की छात्राओं ने थाना कंपू का शैक्षणिक भ्रमण किया। यहाँ

उन्हें पुलिस थाने की कार्यप्रणाली, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, कानून-व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, महिला एवं बाल संरक्षण और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को पुलिस व्यवस्था से परिचित कराना और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ग्वालियर पुलिस के अनुसार, अभियान के माध्यम से युवाओं को कानून के प्रति जागरूक, सुरक्षा के प्रति सजग और सामाजिक दायित्वों के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

पड़ाव थाना प्रभारी ने द्वारकापुरी विकास समिति के रहवासियों को किया सतर्क अवैध कार्बाइड गन और आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखे चलाने पर हो सकती है जेल

ग्वालियर जीएनएस
दीपावली के दौरान कार्बाइड गन और आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है। पड़ाव थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव ने द्वारकापुरी विकास समिति के रहवासियों से संपर्क कर ऐसे खतरनाक और अवैध पटाखों से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों पर नजर रखने और उन्हें इनके इस्तेमाल के खतरे समझाने की अपील की। थाना प्रभारी ने बताया कि



कुछ कंपनियों और निजी दुकानदारों द्वारा चोरी-छिपे कार्बाइड गन सहित अन्य खतरनाक पटाखों की आपूर्ति किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। बच्चे नासमझी में इनका

इस्तेमाल कर खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने रहवासियों से अपील की कि कार्बाइड गन या इसी तरह

के अवैध पटाखों की बिक्री की जानकारी मिलने पर पुलिस को गोपनीय रूप से सूचित करें। खतरनाक पटाखों का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल भी संभव है। बैठक में द्वारकापुरी विकास समिति के संरक्षक यशवंत सिंह कौरव, डॉ. राजकुमार दत्ता, अजय अस्थाना, जीएस जायसवाल, बीएन तिवारी, गुड्डू जैन, श्री सोमवंशी, सुभाष बाबू श्रीवास्तव, रेणुका दत्ता और अंकित शर्मा सहित कई कॉलोनीवासी उपस्थित रहे।

दतिया महाराजा अरुणादित्य देव का बलबंत मंडल ने किया सम्मान



दतिया जीएनएस
श्रीरामलीला आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक एवं दतिया महाराजा अरुणादित्य देव का बुधवार को मुड़ियन का कुआं स्थित संदीप कवि के निवास पर बलबंत मंडल, दतिया की ओर से सम्मान किया गया। इस दौरान महाराजा को पुष्पहार पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल भेंट किया गया। स्वस्तिवाचन के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया गया।

इस अवसर पर बलबंत मंडल, दतिया के संचालक राजेश लिटोरिया, संजय भट्ट, रामकुमार भट्ट, शैलेन्द्र बुधौलिया, विक्रम बुंदेला, महेश पाठक, जॉली शुक्ला और अभय शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बलबंत मंडल की ओर से इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रीरामलीला मंचन में शामिल कलाकारों की टीम ने सहभागिता की।

पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर एक दिसंबर से जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेगा श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकार सुरक्षित होगा तो समाज सुरक्षित होगा : शास्त्री

दतिया जीएनएस
मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की छठवीं प्रदेश कार्यसमिति की बैठक एवं प्रांतीय सम्मेलन बुधवार को दतिया में आयोजित किया गया। प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दतिया विधायक घनश्याम सिंह, पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और रतनगढ़ धाम के महंत पं. राजेश कटारे विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार सुरक्षा कानून का समर्थन करते हुए कहा कि संत विचारक होता है और पत्रकार प्रचारक। समाज को जगाने वाले पत्रकारों को कई बार कठिन परिस्थितियों

का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों की एकजुटता से व्यवस्था बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षित होगा तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने संघ की अगली बैठक फरवरी में बागेश्वर धाम में आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया। **एक दिसंबर से जिला स्तर पर आंदोलन**
सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने की रणनीति पर चर्चा हुई। संघ के प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया ने घोषणा की कि एक दिसंबर से प्रदेश की सभी जिला इकाइयां अपने-अपने जिलों में धरना-प्रदर्शन करेंगी और सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन सौंपेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर अग्रवाल ने संगठन की उपलब्धियां बताते हुए कानून लागू करने में हो रही देरी पर चिंता जताई और



आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। छतरपुर जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह सेगर, शाजापुर जिलाध्यक्ष अभिषेक सक्सेना, उमरिया जिलाध्यक्ष चंद्रकांत दुबे, अशोकनगर जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा और प्रदेश सचिव मेहदी हसन ने भी पत्रकार सुरक्षा कानून

लागू करने की मांग उठाई। **पत्रकार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं**
पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया के व्यक्तित्व और लेखन का उल्लेख करते हुए शायराना अंदाज में अपनी बात रखी। विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि लोकतंत्र

को मजबूत बनाए रखने में पत्रकारों की अहम भूमिका है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और पत्रकार मिलकर काम करें तो जिले का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के काम की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होती और उन्हें

समाचार संकलन के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों को सार्वजनिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक कामकाज में पत्रकारों के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया। सम्मेलन में प्रदेश महासचिव सुनील त्रिपाठी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष शिशुपाल सिंह तोमर ने आय-व्यय का ब्यौरा रखा। कार्यक्रम का संचालन शासन-संगठन समन्वय समिति के संयोजक रिजवान अहमद सिद्दीकी ने किया। आयोजन समिति के संयोजक मनोज गोस्वामी और जिला इकाई अध्यक्ष नितेंद्र गोस्वामी ने स्वागत उद्बोधन दिया। सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारियों, महिला प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों और प्रदेशभर से आए श्रमजीवी पत्रकारों ने भाग लिया।

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती करें सुनिश्चित: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल, जीएनएस।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सेवाओं की प्रगति, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान, फॉलोअप एवं समय पर संस्थागत भर्ती की नियमित समीक्षा की जाएगी। सभी स्तरों पर अधिकारियों एवं मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित कर अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे।

ई-संजीवनी से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाएं

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए आमजन को सेवा के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपयोगिता के प्रति विश्वास विकसित करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल कहा कि भारत में तकनीक को अपनाने की व्यापक क्षमता का प्रत्यक्ष उदाहरण यूपीआई है। इसी प्रकार

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का प्रभावी उपयोग कर नागरिकों को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-संजीवनी के उपयोग में आने वाली बाधाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता में मौजूद अंतराल की पहचान कर उन्हें दूर किया जाए। आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ सेवा के उपयोग एवं परिणामों की नियमित समीक्षा की जाए, ताकि मरीजों को अनावश्यक आवागमन से राहत मिले।

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर संस्थागत भर्ती सुनिश्चित करें

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं निर्धारित प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत पात्र महिलाओं की जांच तथा उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) की समय पर पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाए। परिवारजनों को नियमित जांच और संस्थागत प्रसव के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से लगभग 30 प्रतिशत ही पर्याप्त समय पूर्व

स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती हो पा रही हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेष कार्ययोजना के अनुरूप समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिन्हित महिलाओं की पहचान के बाद उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, आवश्यक जांच एवं उपचार तथा समय पर संस्थागत भर्ती सुनिश्चित की जाए। आशा एवं एएनएम सहित मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर फॉलोअप की नियमित समीक्षा की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

अनमोल पोर्टल एवं सुमन कमांड सेंटर से होगी प्रभावी निगरानी

समीक्षा में बताया गया कि अनमोल पोर्टल पर लगभग 6.2 लाख गर्भवती महिलाओं का विवरण दर्ज है, जिनमें लगभग 2 लाख महिलाओं को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के रूप में चिन्हित किया गया है। सुमन ईटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से भी इन महिलाओं के फॉलोअप की निगरानी की जा रही है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी संबंधित आशा कार्यकर्ताओं एवं जिला अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने डिजिटल व्यवस्था का प्रभावी उपयोग करते हुए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समयबद्ध निगरानी एवं संस्थागत भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश



दिए। उन्होंने सुमन पंचायत की अवधारणा को प्रोत्साहित करने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति समुदाय की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नवजात शिशुओं एवं गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं एवं आवश्यक उपकरणों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कुपोषण से प्रभावित बच्चों की पहचान, उपचार एवं पोषण पुनर्वास के साथ एनीमिया, दस्त एवं निमोनिया जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम के लिए संचालित कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विभागीय समन्वय, तकनीक एवं मैदानी अमले की सक्रियता के

साथ परिणामों की नियमित समीक्षा आवश्यक है। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करें।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रमुख उपलब्धियां

बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर तक प्रदेश में 90.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में पंजीयन हुआ है तथा 93.4 प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए हैं। एसआरएस 2022-24 के अनुसार प्रदेश की मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 135 है। गर्भवती महिलाओं को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए 35 प्रसूति आईसीयू, 109 प्रथम रेफरल इकाइयां तथा 229 बर्थ वेटिंग होम क्रियाशील हैं।

नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश में 62 विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां (स्ट्रेच), 200 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयां (हब्स), 24 मद्र न्यूबॉर्न केयर यूनिट, 68 बाल गहन चिकित्सा इकाइयां (क्यूएल) तथा 318 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 2 मानव दुग्ध बैंक क्रियाशील हैं, 8 प्रक्रियाधीन हैं तथा 26 लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्ट्रेच में 1,34,317 नवजात शिशुओं, हब्स में 45,982 नवजात शिशुओं

तथा क्यूएल में 1,19,032 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया गया। इसी अवधि में पोषण पुनर्वास केंद्रों में 80,092 बच्चों को सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान स्ट्रेच में 72,595, हब्स में 22,793 तथा क्यूएल में 59,450 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया गया, जबकि पोषण पुनर्वास केंद्रों में 47,912 बच्चों को सेवाएं प्रदान की गईं।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन एवं नवाचार आधारित जन-जागरूकता गतिविधियों में मध्यप्रदेश को अगस्त 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं, एएमबी इंडेक्स 2025-26 में आयरन एवं फोलिक एसिड के निवारक अनुपूरण में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ई-संजीवनी के माध्यम से अप्रैल से सितंबर 2026 तक प्रदेश में 59,914 जनरल टेली-कंसल्टेशन तथा 10,890 विशेषज्ञ टेली-कंसल्टेशन किए गए। मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से भी विशेषज्ञ टेली-कंसल्टेशन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सेवाओं का प्रभावी उपयोग कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. प्रभाकर तिवारी, डॉ. अर्चना मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

भिण्ड कलेक्टर ने जनपद पंचायत गोहद के 05 पंचायत समन्वयक अधिकारियों और 02 सहायक विकास विस्तार अधिकारी को दिया नोटिस

कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्य एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत गोहद के पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री मानसिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री राजेन्द्र शाक्य, पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री गणेशराम शर्मा, पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री जगदीश पवैया, पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री जबर सिंह, सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री पवनप्रताप सिंह

तोमर, सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री लोकेश कोरकू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कलेक्टर श्री जैन ने सूचित किया है कि दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को आकांक्षी ब्लॉक गोहद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में पाया गया कि उक्त सभी के सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कुल स्वीकृत आवासों में पूर्ण हुए आवासों का प्रतिशत कम है।

जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के कार्य एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती जा रही है। क्यों न इस लापरवाही के लिये आपकी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जावे।

उक्त के संबंध में आप अपना जवाब सप्रमाण 07 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। जवाब प्राप्त न होने एवं संतोषजनक न होने की स्थिति में उक्त सभी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भिंड कलेक्टर श्री पंकज जैन और एसएसपी श्री सूरज कुमार वर्मा ने किया अटेर फोर्ट व चंबल तट का औचक निरीक्षण

भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (स्क) महोदय द्वारा थाना अटेर क्षेत्र के ऐतिहासिक अटेर फोर्ट (किला) तथा चंबल नदी के तटीय इलाकों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और विकास कार्यों को गति देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। कलेक्टर और एसपी महोदय ने सबसे पहले अटेर के ऐतिहासिक फोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान



उन्होंने किले की स्थापत्य कला, सुरक्षा व्यवस्था और वहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर महोदय ने कहा कि अटेर का किला क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर है और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने पुरातत्व और स्थानीय

प्रशासन के समन्वय से पर्यटन विकास योजनाएं तैयार करने पर बल दिया, ताकि इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय पटल पर विशेष पहचान मिल सके। इसके पश्चात चंबल नदी के तटीय क्षेत्र/घाटों का निरीक्षण कर अवैध रेत उत्खनन तथा परिवहन से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ह्रासद्वार और पुलिस प्रशासन स्पष्ट निर्देश दिए की अवैध उत्खनन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।

भिण्ड में लाभार्थियों को बड़ी राहत- DBT राशि अब किसी भी बैंक शाखा से नहीं रुकेगी

भिण्ड, जीएनएस।

अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) भिण्ड ने जिले की समस्त वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंक शाखाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (छक्का) से लाभार्थी के खाते में बिना देरी जमा हो। कलेक्टर भिण्ड के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।

कलेक्टर भिण्ड ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित कोई भी बैंक शाखा छक्का के माध्यम से आने वाली शासकीय राशि को किसी भी हालत में

रिजेक्ट या वापस नहीं करेगी। शाखा प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि तत्काल संबंधित लाभार्थी के खाते में क्रेडिट हो।

अब बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि न होना, खाता इनएक्टिव या डोमैट होना, या बैंक के आंतरिक शुल्क का हवाला देकर छक्का राशि रोकना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने वाली शाखा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। छक्का भुगतान आमतौर पर आधार सीडिंग और हक्काट्टू मैपिंग के माध्यम से संचालित होते हैं, इसलिए इससे जुड़ी तकनीकी समस्याओं का

शाखा स्तर पर तुरंत समाधान करना भी अनिवार्य किया गया है।

एलडीएम भिण्ड ने चेताया है कि छक्का राशि जमा न होने या लाभार्थी को परेशानी होने की शिकायत मिलने पर संबंधित शाखा प्रबंधक स्वयं उत्तरदायी होंगे। ऐसे मामले नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि किसी लाभार्थी के खाते में आधार सीडिंग, हक्काट्टू मैपिंग या अन्य तकनीकी त्रुटि की समस्या है, तो बैंक शाखा उसे प्राथमिकता से सहयोग देकर समस्या का त्वरित निराकरण करेगी।

व्यापारियों का 100 फीसदी तक ब्याज और अर्थदंड होगा माफ

फिरोजाबाद, जीएनएस।

बकाया कर को लेकर परेशान व्यापारियों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। शासन ने ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर ब्याज में 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। अर्थदंड भी पूरी तरह माफ किया जाएगा। योजना 16 अक्तूबर से तीन महीने तक प्रभावी रहेगी।

राज्य कर विभाग के अनुसार, 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर पूरी ब्याज राशि और अर्थदंड माफ होगा। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 10 फीसदी ब्याज जमा करना होगा और 90 फीसदी

माफ होगा। एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 25 फीसदी ब्याज जमा करने पर 75 फीसदी की छूट मिलेगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 फीसदी ब्याज जमा करना होगा। इस श्रेणी में भी अर्थदंड पूरी तरह माफ रहेगा। योजना का लाभ लेने के लिए मूल बकाया जमा करना अनिवार्य है।

लंबित मुकदमों में भी मिलेगा लाभ

न्यायालय या ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों के व्यापारी भी शपथपत्र और वाद वापस लेने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं। जिन व्यापारियों ने पहले ही मूल बकाये की पूरी या कुछ राशि जमा

कर दी है, वे भी शेष ब्याज और अर्थदंड पर छूट के पात्र होंगे।

व्यापारियों को विभागीय वेबसाइट comta&.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित धनराशि जमा करने के बाद आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करना जरूरी है। प्रत्येक पंजीकरण या वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) के लिए अलग आवेदन करना होगा। विभाग के अनुसार, सत्यापन के बाद अधिकतम 15 दिनों में आरसी बकाया मुक्त होने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। राज्य कर विभाग ने व्यापारियों की सुविधा के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई है।

महाराजपुरा, गिरवाई रोड और जलालपुर क्षेत्र में दबिश

ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 4 प्रकरण दर्ज

ग्वालियर, जीएनएस।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बुधवार 28 अक्टूबर को विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। विभाग की टीम ने महाराजपुरा, गिरवाई रोड और जलालपुर क्षेत्र में दबिश देकर कुल 190 लीटर अवैध मदिरा जब्त की। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए।

आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान महाराजपुरा क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी के आगे वैष्णवी धाम के पास से विवेक सिंह तोमर के अधिपत्य से 307 पाव देशी मदिरा (प्लेन एवं मसाला) और छह बोतल रम जब्त की गई। मौके से आरोपी फरार हो गया। इस मामले में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी क्रम में आबकारी बल और संबंधित पुलिस थाने की

संयुक्त टीम ने गिरवाई रोड स्थित ढाबों की जांच की। इस दौरान होटल फॉरेस्ट ग्लेड से नौ बीयर कैन और तीन बोतल खुली अंग्रेजी मदिरा जब्त की गई। इस मामले में धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जलालपुर क्षेत्र में पप्पू चौहान के मकान से 52 पाव देशी मदिरा प्लेन, आठ बीयर कैन और 12 पाव देशी मसाला मदिरा जब्त की गई। वहीं, राम बरन कुशवाह के पास से 20 पाव देशी मदिरा प्लेन और 26 बीयर कैन जब्त किए गए। इन दोनों मामलों में भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

आबकारी विभाग के अनुसार, पूरी कार्रवाई में धारा 34(1) के तहत तीन और धारा 34(2) के तहत एक, कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त अवैध मदिरा की कुल मात्रा 190 लीटर और अनुमानित कीमत लगभग 55 हजार रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में की गई। इसमें आबकारी उपनिरीक्षक हरेंद्र मावई, शिवा रघुवंशी और सुरेश पाराशर सहित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पाँच आदतन आरोपी जिला बदर : जिला दण्डाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

ग्वालियर, जीएनएस।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा पाँच आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इन आरोपियों को जिला बदर कर दिया गया है। इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा आदतन आरोपी अमन यादव निवासी बड़ागाँव मुरार, उदयभान

गुर्जर निवासी सिरौल, अरविंद यादव निवासी आर्मी चौराहा के पास बड़ागाँव, राजवीर जाटव निवासी ग्राम रनगाँव हाल निवास सिरौल कॉलोनी एवं नितिन यादव निवासी आर्मी चौराहा बड़ागाँव थाना क्षेत्र मुरार को 6-6 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। इन सभी आरोपियों को ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

डबरा में संदिग्ध खाद के गोदाम पर छापा, संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

ग्वालियर, जीएनएस।
डबरा के शुगर मिल क्षेत्र स्थित एक गोदाम में संदिग्ध खाद मिलने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। गोदाम से करीब 32 टन विभिन्न प्रकार के उर्वरक और एक नामी कंपनी के छपे हुए 358 खाली बैग मिले हैं।

उर्वरकों के वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने गोदाम संचालक निशांत अग्रवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डबरा की लिखित शिकायत पर पुलिस थाना डबरा सिटी में मेसर्स जय

कामतानाथ किसान सेवा केंद्र के प्रोपराइटर निशांत अग्रवाल के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धाराओं 4, 5, 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं 5 एवं 7 के तहत अपराध क्रमांक 0651/2026 दर्ज किया गया है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री भानु प्रकाश शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा को शुगर मिल क्षेत्र के एक गोदाम में संदिग्ध खाद रखे होने की सूचना मिली थी। इस पर 26 अक्टूबर की शाम अनुविभागीय कृषि अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में गोदाम खुलवाकर जांच की गई।

भाजपा के चरित्र, उनके नेताओं के कारनामों और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के खोखले दावों पर समाजवादी पार्टी का तीखा हमला

भोपाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर करारा हमला बोलते हुए उनके नेताओं के चरित्र और मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यश भारतीय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा आखिर मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने के लिए कैसे-कैसे %चरित्रवान% लोगों को खोजकर लाती है? इसका उदाहरण देश पहले भी देख चुका है। मोदी सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री रहे एम. जे. अकबर को उस वक्त अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जब 20 से अधिक महिला पत्रकारों ने उनके घटिया व्यवहार और कारनामों को उजागर किया था। एम. जे. अकबर अपनी नाकामी छिपाने के लिए न्यायालय भी गए।

करवा चौथ : प्रेम और विश्वास का पर्व

चौदनी रात, सजी थाली, हाथों में मेहेंदी, मुख पे लाली,
सोलह शृंगार से सजती सुहागिन, प्रेम मूरत मनभावन।



करवा चौथ पावन त्योहार, पति-पत्नी प्रेम का आधार,
निर्जल व्रत रखती नारियाँ, आँखों में सपने मन में प्यार।

पूजा की थाली, दीप ज्योति, चाँद पहले पति की मूरत,
छलनी से देखें चाँद का नूर, प्रेम रिश्ते हों सदा भरपूर।

चाँद निकलता, खिलते हैं चेहरे, प्रेम के रंग लगते गहरे,
पति के हाथों जल ग्रहण, सुखी जीवन कामना करतीं।

ये व्रत नहीं सिर्फ परंपरा का नाम, बसा है प्रेम सम्मान,
साथ निभाने सत्य संकल्प, श्रद्धा महकें जीवन कल्प।

सुख-दुख दोनों बने सहारा, प्रेम से रोशन जीवन सारा,
करवा चौथ का संदेश यही, रिश्तों में प्रेम बसे सही है।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

नाहरगढ़ किले की सड़क दुरुस्त करें, दुर्घटना हुई तो सरकार-प्रशासन जिम्मेदार होगा

जयपुर, जीएनएस।
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, लाइसेंस पर्यटक गाइड एवं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के टूरिस्ट फैसिलिटेटर रवि शंकर धाभाई ने राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाहरगढ़ किले की जर्जर सड़क का तत्काल पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण करवाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अक्टूबर से फरवरी तक पर्यटन सीजन में देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के बावजूद सड़क की बदहाल स्थिति गंभीर दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। रवि शंकर धाभाई ने मुख्यमंत्री से

सड़क के गहरे गड्ढे भरवाने, खतरनाक मोड़ों पर क्रेश बैरियर लगाने, झाड़ियों की कटाई तथा नाहरगढ़-जयपुर मार्ग पर 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात करने की मांग की है। उन्होंने पर्यटक गाइड प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा पूर्व में भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई की जांच कराने का भी आग्रह किया। रविशंकर धाभाई ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पत्र पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई और नाहरगढ़ घाटी में कोई दुर्घटना या जनहानि होती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं संबंधित प्रशासन की होगी।

वामपंथी पार्टियों की बैठक में 01 नवंबर दिल्ली रैली की तैयारी की समीक्षा की

ग्वालियर, जीएनएस।
वामपंथी पार्टियों की बैठक माकपा कार्यालय में पूर्व पार्षद भगवान दास सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एडवोकेट कौशल शर्मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रामविलास गोस्वामी और भाकपा माले के मयंक रावत उपस्थित रहे बैठक में 01 नवंबर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली की तैयारी की समीक्षा की और गली मोहल्ले में चल रहे अभियान को तेज करने की योजना तैयार की गई।



बैठक में मजदूर और किसानों के बीच में पर्वे वितरित कर जत्थे तैयार किए जाएं इसकी भी चर्चा की गई। 01 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में देश भर के

लाखों नागरिक पहुंचेंगे वोट चोरी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के स्तीफे और एस आई यार रद्द करने की मांग को लेकर ग्वालियर से 31 अक्टूबर से ही

जत्थे रवाने होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संजीव राजपूत, अशोक पाठक, शैलेश परमार, प्रकाश वर्मा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अखिलेश यादव, रामबाबू जाटव, जितेंद्र आर्य, प्रीति सिंह, श्याम यादव, बीपी गणक, बीरबल चैन और भाकपा माले के विनोद रावत, सुल्ताना बानो, मलखान सिंह, अशोक खान, आदि ने आम नागरिकों से वामपंथी जत्थों के साथ दिल्ली चलने की अपील की है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया है।

दिवाली से पहले नगर निगम का विशेष सफाई अभियान, चार मुख्य मार्गों से हटाई धूल

ग्वालियर, जीएनएस।
दिवाली के पावन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर में विशेष साफ-सफाई और स्वच्छता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी के सख्त निर्देशानुसार शहर की सड़कों पर डस्ट फ्री रखने के लिए सड़कों पर जमी धूल और गंदगी को हटाने की कार्रवाई की गई।

मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा

आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर की सुंदरता और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्य मार्गों और सड़कों पर धूल हटाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान सड़कों पर फैली धूल को पूरी तरह से साफ किया गया, जिससे शहरवासियों को स्वच्छ और धूलमुक्त वातावरण मिल सके। नगर निगम द्वारा शहर में 132 मुख्य मार्गों को चिह्नित किया गया है, जिसमें सफाई अभियान चलाया जाएगा।

जिसके तहत आज स्वास्थ्य अधिकारी श्री किशोर चौहान के

निर्देशन में वार्ड क्रमांक 54 में कंपू आमखो पर 1000 बिस्तर अस्पताल मुख्य मार्ग के फुटपाथ पर जेटिंग मशीन से धुलाई कराई गई एवं सड़कों से धूल साफ कराई गई। इस दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री रामचंद्र धौलपुरिया, जेड एच.ओ श्री विजय कुमार, डब्ल्यूएचओ श्री अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही बहोडापुर से रामाजी का पुरा, कटोराताल रोड, दीनदयाल नगर गेट नम्बर 1 तक के मार्गों एवं डिवाइडरों की धूल को साफ किया गया।

खुले में कचरा जलाने पर वसुला 1000 का जुर्माना

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार-बार समझाने के बाद भी सड़क पर कचरा फैकने, जलाने एवं गंदगी फैलाने से नही मानने वालों के खिलाफ निरंतर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ निरंतर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज वार्ड 14 के अंतर्गत आने वाले सेवानगर के नूरगंज क्षेत्र में कुरैषी मोहल्ला निवासी श्री जरीफ खान को खुले में कचरा जलाते हुए पकड़ा गया। नियमों का उल्लंघन करने और प्रदूषण फैलाने के आरोप में उन पर तत्काल 1,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। कार्यवाही के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री शरण कुमार, जेडएचओ श्री रवि करोसिया, डब्ल्यूएचओ श्री प्रमोद करोसिया आदि उपस्थित रहे।

हिन्दी दैनिक

श्रमसाधना

आपकी दुःख की छाड़ी में

श्रमसाधना सदैव आपके साथ है

उठावनी/रसम पगड़ी का प्रकाशन निःशुल्क

सम्पर्क करें

ग्वालियर शिवपुरी

☎ 0751-2625029 ☎ 07492-232149

☎ 9074257600 ☎ 8251071286

E-mail : shramsadhnagwl@gmail.com

डिवाइडरों और सड़कों के किनारे की जा रही है साफ-सफाई व सौंदर्यीकरण

ग्वालियर, जीएनएस।
नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा शहर के डिवाइडरों एवं सड़क किनारे के क्षेत्रों की साफ-सफाई, व्यवस्थित रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नोडल अधिकारी पार्क श्री मुकेश बंसल ने जानकारी देते हुये बताया कि निगमायुक्त श्री अभिषेक चौधरी के निर्देशन में पार्क विभाग द्वारा निरंतर डिवाइडरों की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत आज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित स्थलों पर उद्यान विभाग

की टीम के माध्यम से कार्य कराया गया। इसके तहत उद्यान निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह राजावत द्वारा पुरानी छावनी से मोती झील तक रोड डिवाइडर, उद्यान पर्यवेक्षक श्री दिनेश कुशवाहा द्वारा लालटिपारा रोड किनारे लगे खरपतवार एवं डीडी नगर महाराजा कॉम्पलेक्स डिवाइडर पर, उद्यान पर्यवेक्षक श्री सुभाष शाक्य द्वारा सिंधिया कन्या विद्यालय से नवीन पड़ाव पुल तक रोड डिवाइडर एवं उद्यान पर्यवेक्षक द्वारा श्री राजकुमार नागर द्वारा शिरोल रोड फुटपाथ की साफ सफाई कराई गई।

जनगणना 2027: निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी तीन दिन में उपलब्ध कराएं

ग्वालियर, जीएनएस।
जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या गणना की तैयारियों को लेकर नगर निगम ग्वालियर द्वारा आवश्यक जानकारी संकलित की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम के अपर आयुक्त एवं नगर जनगणना अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर को पत्र जारी कर नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में संचालित निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत

जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र के अनुसार, भारत सरकार के राजपत्र, गृह मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के प्रावधानों के तहत स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों से सहायता प्राप्त तथा अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी जनगणना कार्य के लिए संकलित की जानी है। इसमें सफाई संरक्षकों को छोड़कर संबंधित अधिकारियों एवं

कर्मचारियों की जानकारी शामिल की जाएगी। पत्र में निर्देशित किया गया है कि निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार जानकारी तैयार कर पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी दोनों रूपों में उपलब्ध कराई जाए। सॉफ्टकॉपी ई-मेल gwannw@vx@gmail.com पर एक्सेल शीट के रूप में भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, हार्ड कॉपी नगर निगम के बाल भवन कार्यालय में जमा कराई जानी है। नगर जनगणना

अधिकारी ने निर्देशों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जा सकें। पत्र में जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 का उल्लेख करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में बाधा उत्पन्न करने अथवा वैधानिक निर्देशों के पालन में जानबूझकर अवरोध पैदा करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

तीन राजस्व कर संग्रहक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

ग्वालियर, जीएनएस।
राजस्व वसूली समीक्षा के दौरान ट्रेड लायसेंस नहीं बनाये जाने एवं पुराने ट्रेड लायसेंस का नवीनीकरण लक्ष्य के अनुरूप नहीं करने पर पर तीन राजस्व कर संग्रहकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। अपर आयुक्त श्री प्रदीप तोमर द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप नवीन टेड लाइसेंस नहीं बनाये जाने एवं पुरानी ट्रेड लायसेंस का नवीनीकरण लक्ष्य के अनुरूप नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की गई। जिसको लेकर कार्य में लापरवाही करने वाले तीन राजस्व करसंग्रहकों को नोटिस जारी किया गया है।

जिसमें राजस्व कर संग्रहक क्षेत्र क्रमांक 017 श्री नितेश शिवहरे को निर्धारित 20 ट्रेड लायसेंस बनाने का लक्ष्य दिया था परंतु उनके द्वारा 2 ही ट्रेड लायसेंस बनाये गए। इसके साथ ही राजस्व कर संग्रहक क्षेत्र क्रमांक 03 श्री विशाल जाटव को निर्धारित 20 ट्रेड लायसेंस बनाने का लक्ष्य दिया था परंतु उनके द्वारा 2 ही ट्रेड लायसेंस बनाये गए एवं राजस्व कर संग्रहक क्षेत्र क्रमांक 05 श्री मयंक श्रीवास्तव को निर्धारित 40 ट्रेड लायसेंस बनाने का लक्ष्य दिया था परंतु उनके द्वारा 3 ही ट्रेड लायसेंस बनाये गए। जिसके चलते उक्त तीनों राजस्व कर संग्रहकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

मूर्तियों और पार्कों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, विधायक समेत 10 को नोटिस

मूर्तियों और पार्कों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, विधायक समेत 10 को नोटिस
फिरोजाबाद, जीएनएस।
महापुरुषों की मूर्तियों, द्वार और पार्कों के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग को लेकर दायर परिवाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने वर्तमान विधायक मनीष असीजा समेत तत्कालीन नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। सभी को 31 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया गया है। शिवसेना जिला प्रमुख पं. राजीव कुमार शर्मा ने अधिवक्ता संजीव कुलश्रेष्ठ के माध्यम से

न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। अधिवक्ता के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के कार्यकाल में कराए गए मूर्ति, द्वार और पार्क निर्माण से जुड़ी पत्रावलियां नगर निगम में उपलब्ध नहीं हैं। जबकि बिल-बाउचर और ऑर्डरशीट में इन कार्यों के लिए धनराशि जारी किए जाने का उल्लेख है। परिवाद में आरोप है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की मूर्तियां जयपुर में बनवाने के लिए भेजी गई थीं, लेकिन अब तक वापस नहीं आईं। निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपये के सरकारी धन के कथित हेरफेर का आरोप भी लगाया गया है। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया

कि निर्माण और मूर्तियों से संबंधित पत्रावली उपलब्ध न होने की सूचना 23 सितंबर 2020 को तत्कालीन सहायक अभियंता अतुल पांडेय के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के माध्यम से दी गई थी। इसमें निर्माण लिपिक सुरेंद्र रावत और प्रमोद यादव की आख्या भी शामिल बताई गई है। न्यायालय ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारियों डीके सिन्हा और अनिल कुमार, सहायक अभियंताओं दिनेश सचान व रामशंकर राम, अवर अभियंताओं प्रभाकर निरंजन व ओपी निगम, सहायक अभियंता अतुल पांडेय, निर्माण लिपिक सुरेंद्र रावत, प्रमोद यादव समेत संबंधित पटल सहायकों।

मुख्य मार्गों पर कराई पेंच रिपेयरिंग

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं सुगम यातायात के लिए सड़कों पर पेंच रिपेयरिंग का कार्य निरंतर तेजी के साथ किया जा रहा है। नोडल अधिकारी पेंच रिपेयरिंग श्री अमित गुप्ता ने बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार निगम के अमले द्वारा निरंतर सुगम यातायात एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न सड़कों पर पेंच रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। जिसके तहत आज कस्तुरबा मेडिकल से कम्पू गुडा गुडी नाका रोड, टाऊन कॉलोनी न्यू कलेक्ट्रेट के पास, गेंडे वाली सड़क सूबे वाली गली, महेशपुरा, चिरवाई नाका पिपरोली रोड, पिंटो पार्क इण्डस्ट्रीयल एरिया आदर्ष नगर, लोहिया बाजार।

अस्थायी अतिक्रमण हटाकर यातायात को बनाया सुगम

ग्वालियर, जीएनएस।
नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए मदाखलत विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान यातायात में बाधक हाथ ठेलों, फुटपाथों पर लगाए गए फड़ों एवं अन्य अस्थायी अतिक्रमण को हटवाकर मार्गों को आवागमन के लिए सुचारू कराया गया। नगर निगम के नोडल अधिकारी मदाखलत श्री केशव सिंह चौहान के निर्देशन में मदाखलत अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा पूर्व विधानसभा अंतर्गत गांधी रोड पर कलेक्टर बंगले के गेट के बाहर फुटपाथ पर

बैठे भिखारियों का सामान जप्त कर हटाया गया। इसके बाद दीनदयाल नगर में कॉम्पलैक्स के अन्दर से काउन्टर जप्त कर हाथ ठेले काउन्टर को हटाने की सख्त हिदायत दी गई एवं जप्त किया सामान को मदाखलत कार्यालय में जमा कराया गया। इसके साथ ही ग्वालियर विधानसभा अंतर्गत मदाखलत अधिकारी श्री रवि कुमार कोरी के निर्देशन में कॉलोनीपुरा घास मंडी में ईट, पत्थरों सीमेंट बजरी से बनी पक्की बाउंड्री को एवं अन्य स्थाई अतिक्रमण को तुड़ाई की गई तथा अवैध अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही दक्षिण विधानसभा अंतर्गत माधवगंज चौराहे से रॉक्सो पुल तक रोड पर अतिक्रमण किए हुए हाथ ठेलों को हटवाने की कार्यवाही की गई।

कचरा ठियों के साफ करने का अभियान जारी

ग्वालियर, जीएनएस।
नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार शहर में ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत आज नगर निगम ने अभियान चलाकर 6 ब्लैक स्पॉट खत्म किए हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत थीम के तहत शहर में सालों से बने ब्लैक स्पॉट कचरा ठियों को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खत्म किया जा रहा है। इसके बाद फिर से लोग वहां पर कचरा नहीं डाल सके, इसके लिए प्रतिदिन वहां की निगरानी का जिम्मा आईसी टीम को दिया गया है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने सागरताल रोड पर, बटेश्वर रोड, गोवर्धन कॉलोनी, गल्लू कोठार, गुर्जर चौक एवं तिवारी जी के प्लॉट सहित अन्य कचरा ठियों को समाप्त किया गया।

गरबा-डांडिया की धुन पर झूमीं महिलाएं, प्रियंका बनीं 'रास गरबा क्वीन'

फिरोजाबाद, जीएनएस।
पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने गरबा और डांडिया की धुन पर जमकर धमाल मचाया। मौका था टीम मित्रम की ओर से 24 अक्टूबर को क्लार्क्स इन में आयोजित 'रास गरबा 2.0' का। रंगारंग प्रस्तुतियों, प्रतियोगिताओं और मनोरंजक गतिविधियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद नृत्य अकादमी की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। आरती के बाद गरबा और डांडिया का दौर शुरू



हुआ। संगीत की धुन पर महिलाओं ने उत्साह के साथ नृत्य किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'रास गरबा क्वीन' प्रतियोगिता रही।

इसमें प्रियंका मित्तल ने खिताब अपने नाम किया। वहीं, सरप्राइज गतिविधियों, आकर्षक उपहारों और लकी विनर्स की घोषणा ने

प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एपी ज्वेलर्स रहे। आयोजन को सफल बनाने में सोना चांदी, क्लासिक बैगल्स, वृन्सा, मोडिशा, प्रयताक्षा ओवरसीज, मित्रम, क्राफ्टी बाय नूपुर, डब्ल्यूसीसी और लक्स होम्ज डेकोर का सहयोग रहा। आयोजक नीमा पालीवाल, पारुल मल्होत्रा, नेहा गुप्ता, महिमा सिंघल, दीपाली सिंघल और सोनल सिंघल ने अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार जताया।

घंटाघर की जमीन पर इंटरलॉकिंग के विरोध में उतरे व्यापारी, 48 घंटे का अल्टीमेटम

व्यापार मंडल और वैश्य समाज ने किया प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
फिरोजाबाद, जीएनएस।
शहर की ऐतिहासिक धरोहर घंटाघर के पुनर्निर्माण और उसकी विवादित भूमि पर इंटरलॉकिंग कराए जाने के विरोध में बुधवार को व्यापार मंडल और वैश्य समाज के लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए व्यापारियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

की। नगर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी ने कहा कि घंटाघर शहर की ऐतिहासिक पहचान है। इसे हटाए जाने के बाद अब तक मूल स्थान पर दोबारा निर्माण नहीं कराया गया है। दूसरी ओर, विवादित भूमि पर गोयल रेस्टोरेंट की ओर से इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि

जब भूमि से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो वहां निर्माण कार्य किस आधार पर कराया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने गोयल रेस्टोरेंट के कथित अवैध निर्माण की भी जांच कराने की मांग की। कहा कि इस संबंध में विकास प्राधिकरण में शिकायतें की जा चुकी हैं और नोटिस जारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। निर्माण के स्वीकृत मानचित्र और अनुमतियों की जांच कर

अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार बंद करेंगे ज्ञापन में घंटाघर की विवादित भूमि को सुरक्षित रखने, कथित अवैध निर्माण की जांच कराने और घंटाघर का मूल स्थान पर ऐतिहासिक स्वरूप में पुनर्निर्माण कराने की मांग की गई। व्यापारियों ने 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर बाजार बंद कर आंदोलन करने की चेतावनी दी।

दीपावली से पहले मिठाई में मिलावट और तौल में गड़बड़ी रोकने की मांग, जिला प्रशासन को वैधानिक नोटिस

शिवपुरी, जीएनएस। दीपावली पर्व से पहले मिठाइयों में कथित मिलावट, मावा-पनीर की गुणवत्ता, ड्राई फ्रूट की पैकिंग और मिठाई के डिब्बों सहित तौल किए जाने के मामलों को लेकर जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने 27 अक्टूबर 2026 को धारा 80 सीपीसी के तहत कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा श्रम कार्यालय के निरीक्षक को वैधानिक

सूचना पत्र भेजकर जनहित से जुड़े मामलों में शीघ्र ठोस कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता विजय तिवारी ने नोटिस में आरोप लगाया है कि त्योहार के दौरान कुछ मिठाई विक्रेताओं द्वारा महंगी मिठाइयों की पैकिंग में डिब्बों का वजन शामिल कर उपभोक्ताओं से निर्धारित मात्रा से कम मिठाई दिए जाने की शिकायतें सामने आती हैं। उन्होंने काजू कतली और अन्य महंगी मिठाइयों के पैकेटों का उदाहरण देते हुए शुद्ध वजन की निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता बताई है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को मिठाई की वास्तविक मात्रा के

अनुसार ही भुगतान करना चाहिए। नोटिस में ड्राई फ्रूट की स्वयं की गई पैकिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि कुछ प्रतिष्ठानों में पैकेटों पर वजन, उपयोग की अंतिम तिथि और अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किए जाते। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पैकिंग, लेबलिंग, लाइसेंस और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े नियमों के पालन की जांच कराने की मांग की है। विजय तिवारी ने दीपावली के दौरान बड़े पैमाने पर मिठाइयों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले मावा, पनीर, दूध और खाद्य तेल की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता

जताई है। नोटिस में आशंका व्यक्त की गई है कि बाहर से आने वाले कथित मिलावटी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल मिठाई निर्माण में किया जा सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से विशेष जांच दल गठित कर संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच, नमूने लेने और नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। नोटिस में मोडिफाइड वाहनों और ठेलों के माध्यम से मोमोज, पिज्जा, पास्ता एवं बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खाद्य तेल और अन्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच का मुद्दा भी उठाया गया है।

अधिवक्ता ने बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण की आवश्यकता बताई है। अधिवक्ता विजय तिवारी के अनुसार, उन्होंने 5 जनवरी 2026 को भी मोडिफाइड वाहनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की बिक्री के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचना पत्र भेजा था। उनका कहना है कि उस मामले में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत नहीं कराया गया। वैधानिक सूचना पत्र के माध्यम से विजय तिवारी ने संबंधित अधिकारियों से जनहित के मुद्दों पर शीघ्र ठोस कार्रवाई

करने तथा की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। दीपावली जैसे बड़े पर्व से पहले उठाए गए इन मुद्दों के बीच खाद्य सुरक्षा, सही तौल और पारदर्शी व्यापार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों की सक्रियता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, नोटिस में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित विभागों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही उनकी पुष्टि हो सकेगी

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर शिवपुरी की पुरानी जेल में अमर शहीद तात्या टोपे को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात

शिवपुरी, जीएनएस। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, 1 नवंबर 2026 के अवसर पर शिवपुरी शहर के ऐतिहासिक पुरानी जेल परिसर में अमर शहीद तात्या टोपे के स्मरण, माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि सह विचार पत्रकार वार्ता कार्यक्रम के आयोजन की सूचना जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित की गई है। इस पहल का उद्देश्य देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को नमन करने के साथ शिवपुरी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस संबंध में शिवपुरी विधायक देवेन्द्र जैन, जिला पुलिस अधीक्षक यंगचेंग डोलकर भूटिया तथा पुष्कल प्रताप सिंह, लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य अभियंता एवं जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC), शिवपुरी के अतिरिक्त प्रभार से संबंधित अधिकारी।



शिवपुरी एसडीएम अनुपम शुक्ला, शिवपुरी तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा को सूचना पत्र कार्यक्रम आयोजक मंडल ने दिया है। उपरोक्त आयोजन के माध्यम से पत्रकारों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की सहभागिता से राष्ट्रभक्ति, ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और जनहित से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। आयोजकों ने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं गरिमायुक्त ढंग से संपन्न कराने तथा स्वच्छता, अनुशासन और प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य शिवपुरी की ऐतिहासिक पुरानी जेल को उसके ऐतिहासिक

महत्व के अनुरूप पहचान दिलाना और इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की संभावनाओं को सामने लाना है। आयोजकों का मानना है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर ऐतिहासिक स्थलों का स्मरण नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। आयोजकों ने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से अपेक्षा की है कि वे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, पर्यटन विकास और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े इन विषयों पर सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। इस आयोजन की पहल में

वरिष्ठ अधिवक्ता रूप किशोर वशिष्ठ (रूप दादा), महेंद्र सिंह सिकरवार (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबद्ध), जसमन सिंह मौर्य (सहायक संपादक, दैनिक श्रमसाधना), आशा नीम (पंचमहल केसरी, जिला ब्यूरो चीफ), नरेंद्र कुमार पत्रकार शायद खान पत्रकार सहित अन्य पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे। सभी ने शिवपुरी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, अमर शहीद तात्या टोपे के सम्मान, पर्यटन विकास तथा जैसे जनहित के विषयों को प्रमुखता से उठाने की पहल की है। उल्लेखनीय है कि यह पहल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रखकर शिवपुरी के इतिहास, शहीदों के सम्मान, पर्यटन विकास और जनहित के मुद्दों को व्यापक स्तर पर सामने लाने का प्रयास है।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने केदारपुर लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण, लिगेसी वेस्ट का तत्काल निराकरण करने के लिए निर्देश



ग्वालियर, जीएनएस। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने आज गुरुवार को केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर वहां संचालित कचरा प्रबंधन एवं प्रसंस्करण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 1200 टन प्रतिदिन क्षमता वाले कचरा प्रसंस्करण प्लांट का अवलोकन किया तथा प्लांट की कार्यप्रणाली और कचरे के निष्पादन से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती चौहान ने लैंडफिल साइट पर लंबे समय से जमा लिगेसी वेस्ट (पुराने अपशिष्ट) के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए उसे तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने कचरे का

वैज्ञानिक पद्धति से प्रसंस्करण एवं निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लैंडफिल साइट पर जमा अपशिष्ट का शीघ्र निराकरण हो सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कचरा प्रसंस्करण एवं निष्पादन से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, साइट पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखते हुए स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन किया जाए। उल्लेखनीय है कि केदारपुर लैंडफिल साइट शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां जमा पुराने कचरे का समयबद्ध निराकरण होने से भूमि का बेहतर उपयोग करने, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी।

प्रदेश में 30 अक्टूबर को एक लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों और विभागीय संस्थाओं में चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान

स्वच्छता अभियान 6.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल देखरेख संस्थाओं और महिला आश्रय गृहों में होंगी विशेष गतिविधियां
भोपाल, जीएनएस। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार %विशेष अभियान 6.0% के अंतर्गत प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल देखरेख संस्थाओं, वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास और शक्ति सदन में व्यापक स्तर पर स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान का उद्देश्य विभागीय संस्थाओं को स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है। अभियान के अंतर्गत मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 से जुड़े जिला एवं परियोजना कार्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में

विशेष साफ-सफाई की जाएगी। कार्यालयों और केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए आकर्षक वॉल पेंटिंग, रंग-रोगन, आवश्यक मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परिसर में अनुपयोगी एवं अव्यवस्थित स्थानों को व्यवस्थित कर उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। इसके अंतर्गत पौधरोपण, जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन तथा इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं, वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास और शक्ति सदन में पानी की टंकियों की सफाई, शौचालयों की सैनिटाइजेशन तथा खिड़कियों की जालियां सहित संस्थागत परिसरों की विशेष साफ-सफाई की जाएगी। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने

के लिए चित्रकला और फैसी ड्रेस प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। अभियान के दौरान स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित किया जाएगा। **स्वच्छता के साथ जनसमस्याओं के समाधान पर भी विशेष जोर:** राज्य में 30 अक्टूबर को जनसमस्या निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। इस दौरान पोषण सेवाओं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित शिकायतों के अधिकतम निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराना है। अभियान की प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं को स्वच्छता कार्यों के पहले और बाद के छायाचित्र लेने तथा गतिविधियों का विवरण संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के संरक्षक बने मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह

ग्वालियर, जीएनएस। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा उद्घाटनिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह को दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (छष्टष्टु) का संरक्षक नियुक्त किया गया है। काउंसिल के निदेशक मंडल ने 27 अक्टूबर को आयोजित बैठक में उनके मनोनयन को अनुमोदित किया। मंत्री श्री कुशवाह

दिव्यांग क्रिकेट के विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काउंसिल को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे। मंत्री श्री कुशवाह लंबे समय से दिव्यांगजनों के कल्याण, गरिमा और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके अनुभव एवं मार्गदर्शन से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर

प्रतिनिधित्व करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों को गति मिलेगी। दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री राजेश भारद्वाज ने मंत्री श्री कुशवाह द्वारा संरक्षक बनने का आमंत्रण स्वीकार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति श्री कुशवाह का समर्पण प्रेरणादायक है। उनका मार्गदर्शन खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा।

जिले के वृंदावन ग्रामों में भी होंगी 'गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना' के तहत प्रतियोगिताएं

ग्वालियर, जीएनएस। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत ग्वालियर जिले के वृंदावन ग्रामों में भी गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत देशी गौवंश की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जिले

के वृंदावन ग्राम बेहट में स्थानीय मंडी परिसर, टेकनपुर में पंचायत भवन डबरा व सिमिरियाटाका में पंचायत भवन में यह प्रतियोगितायें 30 व 31 अक्टूबर को रखी गई हैं। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत 30 व 31

अक्टूबर को सुबह व शाम गायों के दूध की माप की जायेगी। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए प्रदान किए जायेंगे। द्वितीय पुरस्कार के तहत 50 हजार और तृतीय पुरस्कार के तहत 25 हजार रुपए प्रदान किए जायेंगे।

पंजाबी परिषद समिति ने सनातन धर्म मंदिर में 14वें वर्ष किया आयोजन, सोलह शृंगार कर पहुंची महिलाएं, चांद के दीदार के बाद खोला व्रत

535 सुहागिनों ने किया सामूहिक करवा चौथ पूजन, 51 सुहागिनों और दंपतियों का सम्मान

ग्वालियर जीएनएस
करवा चौथ पर पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए गुरुवार को पंजाबी परिषद समिति की ओर से सनातन धर्म मंदिर के शांति सभागार में 14वां सामूहिक करवा चौथ आयोजन किया गया। इसमें 535 सुहागिनों ने विधि-विधान से पूजन कर व्रत रखा। सोलह शृंगार से सजी महिलाएं उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजन में शामिल हुईं। समिति ने इस अवसर पर 51 सुहागिनों और दंपतियों का स्वागत कर पुरस्कारों से सम्मानित किया। सामूहिक पूजन शाम चार बजे मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ। पंजाबी समाज के राजू पंडित और रजनी शर्मा ने महिलाओं को विधिवत पूजा-अर्चना कराई और करवा चौथ की कथा सुनाई। सबसे पहले भगवान गणेश और

शिव-पार्वती की पूजा की गई। इसके बाद महिलाओं ने सुंदर ढंग से सजाई गई पूजा की थालियों में दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक गीत गाते हुए थाली घुमाई। कथा के समापन पर महिलाओं ने अपनी सास और परिवार के बड़ों के लिए लाए गए सामान का संकल्प किया तथा उनका आशीर्वाद लिया। रात्रि में चंद्रमा निकलने पर महिलाओं ने छलनी से चांद और फिर अपने पति का दीदार किया। चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की लंबी उम्र की कामना की और इसके बाद व्रत खोला। आयोजन स्थल पर बनाए गए सेल्फी प्वाइंट पर महिलाओं और दंपतियों ने तस्वीरें खिंचवाकर उत्सव का आनंद लिया। इन श्रेणियों में किया सम्मानित : समिति की ओर से 12 नवविवाहिताओं, पांच ऐसे



दंपतियों जिन्होंने पति-पत्नी दोनों ने व्रत रखा, 16 सबसे सुंदर मेहंदी रचाने वाली महिलाओं, 11 सोलह शृंगार से सजी महिलाओं तथा 55 वर्ष से अधिक आयु के दंपतियों सहित कुल 51 सुहागिनों और दंपतियों का सम्मान किया गया। सम्मानित होने वालों में

आस्था नितिन कालरा, श्री एवं श्रीमती सुष्मी कटारिया, नमन और श्रुति सचदेवा, सारिका अरोड़ा, उर्वशी मारवाह, श्री एवं श्रीमती दीपक, आशु, प्रिया, आस्था, लता-रविंद्र पनबदा, छाया-गौरव खुराना और सोदामणि-भूपेंद्र जुनेजा सहित अन्य शामिल रहे।

समिति पदाधिकारियों ने संभाली व्यवस्थाएं : आयोजन में समिति के मुख्य संरक्षक कुलवीर भारद्वाज, अध्यक्ष अशोक मारवाह, संयुक्त अध्यक्ष दिनेश भल्ला, सचिव जीके सूरि, उपाध्यक्ष अजय सपरा और नरेंद्र बेदी, कोषाध्यक्ष आत्म प्रकाश मोंगिया,

व्यवस्थापक प्रमिला मारवाह और रममी आनंद उपस्थित रहे। मुख्य संयोजिका सिम्मी अजीत कुकरेजा, सहसंयोजिका लक्ष्मी जुनेजा तथा ममता बेदी, पूजा शर्मा, रश्मि सूरि, रीना गंडोत्रा और रंजन आनंद ने आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। राजपाल खुराना, रविंद्र पनबदा, अनिल शर्मा बिट्टू, राकेश शर्मा, युवा अध्यक्ष सुधांशु भारद्वाज और उमंग भारद्वाज ने भी सहयोग किया। शहर के हनुमान नगर, आदर्श कॉलोनी, डीबी सिटी, समाधिया कॉलोनी, रतन कॉलोनी, रामबाग कॉलोनी, एलिजाबाग, बसंत विहार, विवेक विहार, चेतकपुरी, हरिशंकरपुरम, सिटी सेंटर, सेवा नगर और विनय नगर सहित पंजाबी बहुल क्षेत्रों में भी करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 3 से 5 किलोमीटर की दौड़

कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस, जिलों में होगी एकता दौड़

ग्वालियर जीएनएस
लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को प्रदेशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों पर 3 से 5 किलोमीटर की %रन फॉर यूनिटी% आयोजित की जाएगी। साथ ही शासकीय कार्यालयों, स्कूलों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाने के साथ विभिन्न कार्यक्रम होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को हुई बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। कार्यक्रमों का उद्देश्य सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करने के साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

जिलों में होगी एकता दौड़

जिला प्रशासन पुलिस बल तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से एकता दौड़ आयोजित करेगा। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, खिलाड़ियों, युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी रहेगी।

अनूप जौहरी सहित दिव्यांगजनों ने दी बधाई और शुभकामनाएं

नारायण सिंह कुशवाह बने दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के संरक्षक

ग्वालियर जीएनएस
दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीसीआई) की बैठक में मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह को काउंसिल का संरक्षक बनाए जाने पर समाजसेवियों और दिव्यांगजनों ने हर्ष व्यक्त किया है। वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय सशक्त आत्मनिर्भर ट्रस्ट, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सलाहकार तथा आरटीआई कार्यकर्ता अनूप जौहरी



ने समस्त दिव्यांगजनों की ओर से मंत्री कुशवाह को बधाई और शुभकामनाएं दीं। डीसीसीआई के अध्यक्ष राजेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में

यह निर्णय लिया गया। अनूप जौहरी ने कहा कि मंत्री कुशवाह हमेशा पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनके संरक्षण से दिव्यांग क्रिकेट को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। बधाई देने वालों में मनोज भिलवार, परमाल सिंह कुशवाह, जीतू यादव, आदिल खान, जाहिर हुसैन, नासिर हुसैन, अनूप परिहार, आकाश पाल, सागर, दिनेश मोरे और मुकेश प्रजापति सहित अन्य लोग शामिल हैं।

15 से अधिक गांवों में जनसंपर्क कर ग्रामीणों को दी दीपावली की शुभकामनाएं सिंधिया ने विकास कार्यों से बढ़ाया ग्वालियर ग्रामीण का मान : गिराज गुर्जर

ग्वालियर जीएनएस
भाजपा ग्वालियर ग्रामीण के पूर्व जिला मंत्री गिराज सिंह गुर्जर ने दीपावली के अवसर पर अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के चौथे दिन गुरुवार को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 15 से अधिक गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और नववर्ष के कैलेंडर वितरित किए। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सहयोग से केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने



ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र को विकास की कई सौगातें दी हैं। इनमें साडा क्षेत्र में 14 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित टेलीकॉम

मैनुफैक्चरिंग जोन, पश्चिमी बायपास, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) और एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं शामिल

हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बायपास से ग्वालियर के पश्चिमी हिस्से के सैकड़ों गांवों को जोड़ने की योजना है। इन विकास कार्यों और परियोजनाओं से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का मान बढ़ा है। ग्रामीणों के लिए यह गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से इन विकास कार्यों के लिए सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त करने की अपील की। गुर्जर ने डबका, मड़ैया, छोदी, आरोली, हस्तिनापुर, निरावली, इंगोरा, फुसवाली, लक्खापुर, तोर, मुख्तयारपुरा, फूलपुरा, रिपुआपुरा, राहुवली और सुमावली सहित 15 से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया।

वर्तमान का बलिदान कर ही भविष्य का निर्माण किया जा सकता है

ग्वालियर जीएनएस
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखी में प्रेरक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता उदयभान रजक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति वर्तमान में संघर्ष करता है और कठिनाइयों को सहन करता है, उसका भविष्य उतना ही उज्ज्वल और सार्थक बनता है। वर्तमान के सुख-सुविधाओं का त्याग कर ही महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष और त्याग व्यक्ति को समृद्ध जीवन के साथ समाज के लिए प्रेरणास्रोत भी बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह बचपन से किए गए संघर्ष और साधना ने उन्हें विश्वभर में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई।

उन्होंने विभिन्न महापुरुषों की संघर्ष गाथाएं और प्रेरक प्रसंग सुनाकर विद्यार्थियों में उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम के अंत में उदयभान रजक ने अपना स्वरचित देशभक्ति और ऊर्जा से भरपूर गीत प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तालियों के साथ उनकी प्रस्तुति की सराहना की। विद्यालय की प्राचार्य राजबाला माथुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ व्याख्याता अश्वनी परमार ने पुष्पहार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उपप्राचार्य संजू तोमर, परीक्षा प्रभारी मनोज कुमार उपाध्याय और वरिष्ठ व्याख्याता अर्चना सहित शिक्षकगण एवं सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रभारी पुष्पा शर्मा ने किया।